सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 20, नई दिल्ली । मंगलवार, 02 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी।

03 तिहाड़ के अंदर केजरीवाल, बाहर समर्थकों का बवाल

06 अब बौद्धिक क्षमता की बढ़त जरूरी

08 भारतीय संस्कृति और इतिहास की झलक मिलती हैं इन प्राचीन गुफाओं में

सड़कों से हटाए जाएंगे 36 करोड़ डीजल/ पेट्रोल वाहन: नितिन गडकरी

संजय बाटला

नई दिल्ली। हाइब्रिड गाड़ियों पर जीएसटी घटाने की वकालत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिज्ञा ली है कि वे देश को 36 करोड़ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से मुक्ति दिलायेंगे. नितिन गडकरी से जब सवाल पूछा गया कि क्या भारत को पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों से मुक्ति दिलाई या जा सकती है तो उन्होंने कहा कि ये 100 फीसदी संभव है. 16 लाख करोड़ रुपये की होगी बचत एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा कि, ऐसा करना कठिन जरूर है पर ये असंभव नहीं है. उन्होंने कहा, ये मेरा लक्ष्य है. गडकरी ने कहा, भारत सलाना 16 लाख करोड़ रुपये ईंधन के आयात पर खर्च करता है. इसे पैसे की बचत किए जाने पर किसानों के जीवन में बदलाव लाया जा सकेगा, देश के गावों में समृद्धि आएगी, युवाओं को रोजगार दिलाया जा सकेगा. सड़क परिवहन मंत्री ने देश की सड़कों पर से पेट्रोल डीजल के कारों को पूरी तरह हटाने के टाइमलाइन बताने से इंकार कर दिया है. हाईब्रिड गाड़ियों पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव नितिन गडकरी ने कहा, हाइब्रिड व्हीकल्स में जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है तो फ्लेक्स इंजन पर 12 फीसदी जीएसटी करने का प्रस्ताव है. उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है जिसपर मंत्रालय विचार कर रहा है. सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर फ्यूल इंपोर्ट को खत्म किया जा सकता है. 5 से 7 वर्ष में दिखेगा बड़ा बदलाव सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि वे 2004 से वैकल्पिक ईंधन की वकालत करते रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में इस दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस बदलाव की तारीख और वर्ष बताना बेहद कठिन है. उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि यह मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं.

चीते से भी तेज चलेंगी अब रेल...

परिवहन विशेष न्यूज

यह चीते से भी तेज स्पीड से दौड़ेगी. जिसकी स्पीड 130 किमी. प्रति घंटे तक होती है. इस ट्रेन के ट्रैक पर उतरने का समय लगभग तय हो गया है. इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद सभी का मन एक बार सफर करने का जरूर करेगा.

नईदिल्ली। देश की पहली लंबी दूरी की लग्जरी ट्रेन ट्रैक पर उतरने को तैयार हो रही है. इसकी स्पीड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह चीते से भी तेज स्पीड से दौड़ेगी. जिसकी स्पीड 130 किमी. प्रति घंटे तक होती है. इस ट्रेन के ट्रैक पर उतरने का समय लगभग तय हो गया है. इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद सभी का मन एक बार सफर करने का जरूर करेगा. रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार बदलाव करता जा रहा है. सेमी हाईस्पीड ट्रेन यानी वंदेभारत से लेकर आम लोगों की राजधानी यानी अमृतभारत ट्रेन दौड़ रही हैं.अब एक और लंबी दूरी की लग्जरी ट्रेन यानी स्लीपर वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रैक पर दौड़ने को तैयार हो रही है. मंत्रालय के अनुसार यह ट्रेन 100 दिन के प्लान में भी शामिल है. इस तरह माना जाए कि सितंबर यह ट्रेन ट्रैक पर आ जाएगी और लोग इस ट्रेन से लंबी दूरी का सफर सुविधाजनक ढंग से पूरी कर सकेंगे. रेलवे के अनुसार स्लीपर वंदेभारत को उन लंबे रूटों पर चलाया जाएगा, जहां पर राजधानी ट्रेनें चल रही हैं और पहुंचने में काफी समय लगाती हैं.

ट्रेन का तेजी से चल रहा है निर्माण. राजधानी जैसी होंगी तीन श्रेणी रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार स्लीपर वंदेभारत एक्सप्रेस में 16 कोच होंगे. इसमें राजधानी की तरह थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी के कोच होंगे. बर्थ, एयर डक्ट, केबल डक्ट, वॉशरूम के डिजाइन भी राजधानी से अलग होंगे. इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किमी. प्रति घंटे होगी, जिससे लंबी दूरी कम समय में पूरी की जा सके. फर्स्ट ऐसी के कोच में होंगी अतिरिक्त सुविधा जिस तरह वंदेभारत में चेयरकार और एग्जक्यूटिव क्लास में फर्क होता है. उसी तरह थर्ड व सेकेंड एसी की तुलना में फर्स्ट एसी में अधिक सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी. इसमें बर्थ और गद्देदार होंगी. कोशिश की जा रही है कि फ्लाइट जैसी सुविधाएं इस श्रेणी के यात्रियों को दी जाएं. इसके अलावा अन्य श्रेणी की तुलना में इसमें खाना-पान भी खास होगा. इसके अलावा इन कोचों में अटेंडेंट की संख्या भी अधिक होगी. जो यात्री के सहयोग के लिए तुरंत मौजूद रहेंगे।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए आज से लागू हो रही नई स्कीम, जानें किन व्हीकल पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक परिवहन संवर्धन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) शुरू की है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लगातार अपना सपोर्ट दे रही है। इसी कड़ी में अब 1 अप्रैल 2024 से देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई स्कीम लागू होने जा रही है। यह स्कीम जुलाई 2024 के आखिर तक जारी रहेगी। भाषा की खबर के मुताबिक, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक परिवहन संवर्धन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) शुरू की है। ईएमपीएस 2024 के तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसका मकसद लगभग 3.33 लाख दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है।

इस बीच, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम-2) कार्यक्रम का दूसरा फेज 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गया है। फेम योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए उपलब्ध थी। नई स्कीम के तहत मिलेगी इतनी छूट

छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 41,000 से अधिक ऐसे वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपये तक होगी। ईएमपीएस 2024 एक कोष के लिहाज से सीमित अवधि की योजना है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार महीनों यानी एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक के लिए 500 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया जाएगा। 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहन को मिलेगा सपोर्ट

भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में हरित परिवहन व्यवस्था और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परिवेश के विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए 13 मार्च को इसकी घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहन को समर्थन देना है। मंत्रालय ने कहा था कि उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें उन्नत बैटरी लगी होगी। इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।

हाईवे पर फिलहाल नहीं बढ़ेंगी टोल दरें, चुनाव आयोग ने लगाई रोक, यह है वजह

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सरकारी उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को हाईवे पर नए यूज़र फीस (टोल) दरों की गणना करने के लिए आगे बढ़ाने को कहा है। लेकिन साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनावों के बाद ही लागू होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सरकारी उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को हाईवे पर नए यूज़र फीस (टोल) दरों की गणना करने के लिए आगे बढ़ाने को कहा है। यह देश भर में ज्यादातर टोल वाले राजमार्ग खंडों पर 1 अप्रैल से सालाना लागू होता है। लेकिन साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनावों के बाद ही लागू होनी चाहिए। पीटीआई के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने NHAI को टोल शुल्क बढ़ोतरी को स्थगित करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के इस संबंध में एक संचार का जवाब दे रहा था। टोल बढ़ोतरी का वार्षिक संशोधन, जिसके औसतन 5 प्रतिशत की सीमा में रहने की उम्मीद थी, देश भर में ज्यादातर टोल वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे खंडों के लिए 1 अप्रैल से लागू होना था। "बिजली शुल्क पर निर्णय के लिए जरूरी प्रक्रिया राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रखी जा सकती है। हालांकि, शुल्क निर्धारण सिर्फ संबंधित राज्य में चुनाव पूरा होने के बाद ही, यानी राज्य में मतदान की तारीख/तारीखों के बाद किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल, 2024 को सड़क मंत्रालय को भेजे एक संचार में कहा, "आयोग के उपरोक्त निर्देशों में उल्लिखित विद्युत शुल्क के संदर्भ में यूज़र फीस को देखा जा सकता है।" एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, टोल फीस में परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मुद्रास्फीति में परिवर्तन के आधार पर दरों को संशोधित करने के लिए एक वार्षिक अभ्यास का हिस्सा है।

नीचे प्रस्तुत कारणों में से आप किसे सड़क दुर्घटना का कारण मानते हैं और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है बताए!

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क सुरक्षा में क्या आ रही है रूकावटे और कौन है इनका जिम्मेदार? अपना विचार व्यक्त करे

1. खराब सड़क बुनियादी ढांचा (जैसे, साइनेज की कमी, गड्ढे)
2. नशे में गाड़ी चलाना और किसी भी दवा के प्रभाव में गाड़ी चलाना
3. पैदल यात्री सुरक्षा (जैसे फुटपाथ पर अतिक्रमण, असुरक्षित क्रॉसिंग)
4. तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना
5. नाबालिग द्वारा वाहन चलाना (बिना वैध लाइसेंस के बच्चों द्वारा वाहन चलाना)
6. नो एंट्री और गलत तरीके से ड्राइविंग
7. सड़क किनारे अवैध पार्किंग
8. यातायात कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन
9. दिल्ली फ़रीदाबाद दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
10. रेड लाइट जंप

आपके द्वारा दिए गए सुझावों/विचारों और राय से हम सब मिलकर सड़क दुर्घटनाएं रोकने का प्रयास कर किसी का जीवन बचा सकते है, अपने विचार व्यक्त कर जनहित और सुरक्षा में सहयोग प्रदान करे।

रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन और परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

पॉट होल सर्वे दिनांक 1 अप्रैल को स्थान: सिद्धदाता रोड, फ़रीदाबाद

Project Name: #Gaddhasur; Pot Hole Kills

सड़क दिन-ब-दिन ख़राब होती जा रही है, या तो इस सड़क को अगली मरम्मत तक बंद कर दें या उचित पैचवर्क के साथ इसकी मरम्मत का काम करें। पिछले साल सड़क की मरम्मत की गई लेकिन 1 महीने के भीतर ही स्थिति सामान्य हो गई, वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में डीसी कार्यालय में सड़क सुरक्षा बैठक में कई बार तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले राजमार्गों के लिए, सम संख्याएं (ईवन नंबर) प्रमुख होती हैं।

क्या आपको पता है भारत में नेशनल हाईवे का नाम कैसे रखा जाता है, यहां जानें

परिवहन विशेष न्यूज

भारत का फैला राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) का जाल देश की परिवहन प्रणाली (ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम) की लाइफलाइन है। हर नेशनल हाईवे को एक नबंर दिया गया है, जो उसकी एक अनोखी भौगोलिक कहानी बया करता है। इन नंबरों को तय करने के पीछे के तरीके को समझने से उस जटिल प्लानिंग का पता चलता है जो इस विशाल सड़क नेटवर्क को आकार देता है।

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भारत में हाईवे के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को नंबर देने का एक तार्किक पैटर्न होता है। सभी महत्वपूर्ण राजमार्गों के लिए, एक या दो अंकों की संख्या का इस्तेमाल किया जाता है।

उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले राजमार्गों के लिए, सम संख्याएं (ईवन नंबर) प्रमुख होती हैं। और ये संख्याएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाती हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 (NH-2) पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। जबकि NH-68 राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले राजमार्ग विषम संख्याओं (ऑड नंबर) वाले सिम्फनी का प्रदर्शन करते हैं। इन विषम संख्याओं का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर संरेखित (एलाइन) होता है। जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में स्थित NH-8, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से को सुशोभित करने वाले NH-87 के बिल्कुल विपरीत है।

इसके अलावा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाले राजमार्गों के संख्यात्मक मान बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि NH-4 अपनी उत्तर-दक्षिण यात्रा पर किसी पूर्वी राज्य को सुशोभित करता है, तो मध्य य पश्चिमी राज्य में इसका समकक्ष अनिवार्य रूप से चार से ज्यादा संख्या वाला होगा।

सहायक राजमार्ग क्या हैं?

तीन अंकों वाली संख्या वाले राजमार्गों को सहायक राजमार्ग (सब्सिडियरी हाईवे) के रूप में जाना जाता है, जो अपने मूल राष्ट्रीय राजमार्गों की जटिल शाखाएं बनाते हैं।

उदाहरण के लिए, एक्सटेंशन 244, 144, और 344 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की शाखाएं हैं। इन सहायक राजमार्ग संख्याओं में पहला अंक उनकी दिशात्मक अभिविन्यास (डायरेक्शनल ओरिएंटेशन) को बताता है। विषम प्रारंभिक अंक पूर्व-पश्चिम प्रक्षेपवक्र (ईस्ट टू वेस्ट ट्रेजेक्ट्री) का इशारा करते हैं। जबकि सम अंक उत्तर-दक्षिण अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) को दर्शाते हैं।

पहचान को और सुव्यवस्थित करने के लिए, सहायक राजमार्ग अपनी तीन अंकों की संख्या के भीतर अक्षरों (ए, बी, सी या डी) का इस्तेमाल करते हैं। ये अक्षर सावधानीपूर्वक विभिन्न सेक्शन के बारे में बताते हैं, जिससे इन सहायक सड़क मार्गों के साथ स्पेसिफिक रूट (विशिष्ट मार्गों) के बारे में बताना आसान हो जाता है।

गर्भवती महिलाओं को क्यों खाना चाहिए मखाना? शरीर की कौन सी 5 कमियों को करता है दूर, जानें

प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भवती मां का सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है. इसके लिए जरूरी है कि ऐसे फूड्स का सेवन करें, जो आपकी और आपके पेट में पल रहे शिशु की सेहत के लिए फायदेमंद हों. मखाना ऐसे ही फायदेमंद फूड्स में एक है. इसमें मौजूद पोषक तत्व ही मखाने को सुपरफूड बनाते हैं. गर्भावस्था के दौरान मखाने खाने से हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं. साथ ही खून की कमी भी दूर होती है. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में मखाने खाने के और क्या फायदे हैं? मखाने में कौन से पोषक तत्व होते हैं? गर्भवती महिला को दिनभर में कितने मखाना खाना सही? इन सवालों के बारे में राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनोकॉलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा ने विस्तार से बताया है.

मखाना सुपरफूड क्यों ?:

डॉ. साहा के मुताबिक, मखाने में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जिंक पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी होते हैं. इसके अलावा मखाने में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए आप इसे स्नैक के रूप में खा सकती हैं. इससे मां के साथ पेट में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है. बेहतर स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के लिए इसमें सभी जरूरतमंद पौष्टिक तत्व मौजूद हैं. इसीलिए इसे सुपरफूड कहा जाता है.

1 दिन में कितने मखाना खाना चाहिए ?:

डॉ. साहा के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को मखाने खाना बेहद फायदेमंद है. भुना मखाना, एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक है. यह पेट के लिए हल्का, खाने में कुरकुरा और स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है. हालांकि, मखाने को अधिक खाने से बचें. इसके लिए बेहतर होगा कि 1 दिन में एक से दो मुट्ठी ही मखाने खाएं.

हड्डियां मजबूत होंगी:

प्रेग्नेंसी में मखाने खाने से शरीर को मजबूती मिलती है. दरअसल, मखाना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है. ऐसे में ये हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है. प्रेग्नेंसी में मखाना खाने से गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद होने वाले हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है. इसके लिए यदि आप मखाने को घी में भूनकर खाती हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा.

खून की कमी सुधारे:

मखाने का सेवन आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है. बता दें कि, प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो जाती है. ऐसे में यदि आप मखाना खाती हैं तो हीमोग्लोबिन के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में आप शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर कर सकती हैं. इसका आप सीमित मात्रा में सेवन कर सकती हैं.

भ्रूण का विकास करे:

मखाना पेट में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है. प्रेग्नेंसी में मखाना खाने से भ्रूण के विकास के लिए फायदेमंद होता है. बता दें कि, मखाना खाने से गर्भवती महिला को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं. इसके अलावा, प्रेग्नेंसी में नियमित रूप से मखाने का सेवन करने से कमजोरी और थकान जैसी कई समस्याएं नहीं होती हैं.

कब्ज से दिलाए राहत:

प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है, जिससे निजात पाना बेहद जरूरी है. इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी डाइट में मखाने को शामिल कर सकती हैं. बता दें कि, मखाना फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके लिए आप मखाने को रोस्ट करके या दूध में उबालकर खा सकती हैं.

अनिद्रा से बचाए:

गर्भावस्था के दौरान मखाने का सेवन करने से नींद अच्छी आती है. दरअसल, कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलावों के कारण अनिद्रा की समस्या हो जाती है. बता दें कि, मखाना आइसोक्यूनोलिन एल्केलॉइड से भरपूर होता है. इसके नियमित सेवन से दिमाग को आराम मिलता है, जिससे नींद अच्छी आती है.

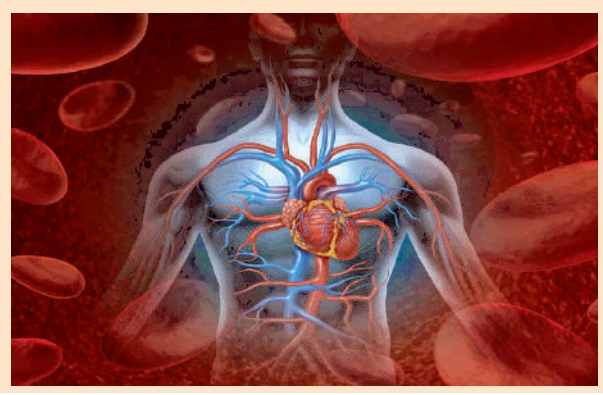

समाज सेवा के साथ स्वस्थ पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से :डॉ. हृदयेश कुमार

स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ हेल्दी फूड ही नहीं बल्कि अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है :डॉ . हृदयेश कुमार

फरीदाबाद से सुनील जांगडा की रिपोर्ट

फरीदाबाद: स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ हेल्दी फूड ही नहीं बल्कि अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। नींद के इसी महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को 'वर्ल्ड स्लीप डे' मनाया जाता है।

अपर्याप्त नींद के कारण होने वाली हृदय संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ. हृदयेश कुमार ने बताया कि जिस तरह भोजन हमारे शरीर की जरूरत है, ठीक वैसे ही पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है।

अगर नींद पूरी होती है तो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करता है और ब्लड प्रेशर भी ठीक बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति नींद की बीमारी, (ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी),से पीड़ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति की नींद रात में बार-बार टूटती है। स्लीप डेफिशियेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ने और कई बार ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है।

ब्लड प्रेशर के अनियंत्रित होने के कारण हार्ट की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। जिन लोगों का हार्ट फंक्शन कमजोर है, उन्हें हार्ट फेलियर की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर के अनियंत्रित होने के कारण हार्ट अटैक, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ सकता है।

रात के समय लम्बे समय तक मोबाइल फोन या किसी अन्य गैजेट के इस्तेमाल करने से भी पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं आती हैं तो इससे आपके हार्ट पर स्ट्रेस (जोर) पड़ता है। स्ट्रेस बढ़ने के मुख्य कारण आपके शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन का निकालना है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। सामान्य तौर पर 24 घंटे में व्यक्ति को 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नींद कम आती है तो वह चिंतित हो जाता है। कई बार कुछ लोग नींद की दवाई का सहारा लेते हैं जिसका शरीर पर खराब असर पड़ता है।

व्यक्ति को इस दवाई की लत पड़ सकती है। नींद भूख की तरह शरीर की जरूरत होती है,जितना ज्यादा बॉडी थकेगी उतना ज्यादा खाने एवं नींद मांगेगी। नींद को बढ़ाने के लिए नींद की दवाओं की बजाय फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से बॉडी को थकाने की कोशिश करनी चाहिए। रोजाना एक्सरसाइज करें,इससे आपका शरीर थकेगा और नींद लंबी एवं गहरी आएगी। हार्ट मरीजों के लिए एक्सरसाइज करना जितना जरूरी है,पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक से नींद न लेने के कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के मरीज को हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है इसलिए हृदय मरीजों को भी पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। स्मोकिंग करने से आपकी नींद और भूख दोनों पर बुरा असर पड़ता है।

अगर आप रात में सोने एवं खाना खाने से पहले स्मोकिंग करते हैं तो आपकी भूख और नींद दोनों खराब होंगी। नींद के डिस्टर्ब होने से ब्लड प्रेशर बढेगा और आपके हार्ट पर स्ट्रेस पड़ेगा इसलिए स्मोकिंग करने से बचें।

जाने आखिर 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है

आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोग पढ़ाई या नौकरी के चलते अपने घर से दूर बहुत दूर दूसरे शहरों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को किराए पर किराएदार बनकर रहना पड़ता है। किराये पर रहने से पहले किरायेदार और मकान मालिक को एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें दोनों पक्षों का नाम, पता, किराए की राशि, किराये की अवधि जैसी अन्य शर्तें और डिटेल शामिल होती हैं। वहीं, अब रेंट एग्रीमेंट की बात करें, तो आपने यह भी देखा होगा कि हमारे देश में ज्यादातर लोग रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने के लिए ही बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर रेट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही क्यों बनता हैं, इसे पूरे साल या फिर उससे ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं बनाया जाता है? यदि आप इसका जवाब नहीं जानते हैं, तो आइये आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक बताते हैं। सिर्फ 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाने की असली वजह ग्यारह महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बढ़ते प्रचलन के पीछे का सबसे बड़ा कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है। इस एक्ट के सेक्शन 17 के मुताबिक, एक साल से कम के लीज समझौतों को रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किराये की अवधि 12 महीने से कम है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी समझौता किया जा सकता है। यह मकान मालिक और किरायेदार दोनों को सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने की परेशानी से बचाता है। यही कारण है कि 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का प्रचलन ज्यादा है। इस प्रकार, इस तरह के शुल्कों से बचने के लिए, आमतौर पर 11 महीने का एग्रीमेंट किया जाता है। इसके अलावा, यदि किराये की अवधि एक वर्ष से कम है, तो स्टांप शुल्क भी बच जाता है, जिसका भुगतान किराए के एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के समय करना पड़ता है। इसलिए मकान मालिक और किरायेदार दोनों पारस्परिक रूप से लीज को रजिस्टर नहीं करने के लिए सहमत होते हैं। अब जानिए , क्या एक साल या उससे ज्यादा के लिए बना सकते हैं रेंट एग्रीमेंट? जब कोई व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करता है तो स्टांप ड्यूटी, किराए की धनराशि और रेंटल अवधि के आधार पर तय की जाती है। कहने का आशय यह है कि किराये की अवधि जितनी लंबी होगी, स्टैंप ड्यूटी भी उतनी ही अधिक लगेगी। इसलिए, जितने अधिक समय के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, उतना ही अधिक पैसा दोनों पार्टियों को देना पड़ता है। जबकि, 11 महीने से कम का एग्रीमेंट/करार करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है। यही वजह है कि ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही किए जाते हैं। इसके पीछे का कारण रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी जैसी अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के खर्च और भीड़भाड़ से बचना होता है। इसके अलावा, यह लैंडलॉर्डस/जमींदारों और किरायेदारों को अनावश्यक शुल्क के बिना किराये का समझौता करने का एक आसान और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है।

पुनर्वास का आश्रयस्थल...

पुनर्वास के मानदंड पर सुक्खू सरकार ने, कांगड़ा एयरपोर्ट विकास के सभी पहलुओं को एक नई परिभाषा दी है। विकास की जरूरतों में महज योजना नहीं, इनसान की सहमति का नया परिदृश्य भी खड़ा करना पड़ता है। भीतर ही भीतर हर विकास की कडियों में मानव की गतिविधियों का संसार भी बसाना पड़ता है। जाहिर तौर पर कांगड़ा एयरपोर्ट सिर्फ विस्तार का नक्शा नहीं, सरकार की इच्छाशक्ति और भविष्य के समर्थन की सहमति भी है। यहां महज विकास का भविष्य नहीं, विस्थापित जनता का भविष्य भी सर्वोपरि दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मुआवजे की राशि वास्तविक कीमत को पांच गुना तक पहुंचा रही है तो कर्मक्षेत्र को भी आश्रय दे रही है। हिमाचल में यह अपनी तरह का फैसला है जहां विस्थापन को पुनर्वास के आश्रय में समझा जा रहा है। बेशक उजडने की सिसकियां कभी कम नहीं होतीं, लेकिन विकास की गति में आर्थिकी के जिस पड़ाव पर हिमाचल खड़ा है, वहां भूमि पर नक्शे भी बड़े करने होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में कांगड़ा एयरपोर्ट का नक्शा लगातार फैलता रहा और अब अपने मुकाम पर आकर बता रहा है कि इसके विस्तार की अनिवार्यता में यह सदी नई कहानी लिखेगी। शायद कल जब एयरपोर्ट विस्तार की खूंटियां स्पष्ट नजर आएंगी, तो हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे, 'एक था गगल का कस्बा' या बताएंगे कि फलां बाजार कांगड़ा एयरपोर्ट ने बसाया। दरअसल विस्थापन को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। अपने घर और आंगन को खोना कोई आसान समाधान नहीं, फिर भी देश के निर्माण में नागरिक योगदान की परिभाषा पर मंथन, सहमति और संरक्षण होना चाहिए। आज एयरपोर्ट विस्तार के बहाने पुनर्वास का खाका और माथा सामने आया है, तो इसकी पैमाइश में सरकार ने हर सूरत इच्छा शक्ति दिखाई है। यह केवल पुनर्वास की नई सुर्खी नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का विस्तार भी है। यानी सरकार चाहे तो किसी भी हद तक जाकर मसलों का हल और जनता की सहमति के आदर्श स्थापित कर सकती है। बावजूद इसके कि मानव संवेदना के हर पहलू के अपने तर्क वितर्क और आस्थाएं रहती हैं, विकास की अपरिहार्यता में कुछ मंजिलें ऐसी भी आएंगी जहां सफलता का सेहरा बहुत कुछ खरीद लेगा। बहरहाल पुनर्वास के लिए मानदंड पर सरकार पांच गुना मुआवजे के अलावा बसाने व कमाने के लिए अधोसंरचना निर्माण का रास्ता भी बना रही है। पुनर्वास का यह मॉडल ऐसी आशा जगा रहा, जहां भविष्य की चुनौतियां पूरी की जा सकती हैं। हम इस परियोजना के कई पहलू देख सकते हैं और यह हिमाचल में टिहरी बांध परियोजना की तरह नागरिक समाज से सीधे मुखातिब है। न्यू टिहरी शहर का निर्माण याद दिलाता है कि विस्थापन के दर्द में पुनर्वास के अर्थ मिल जाएं, तो हर कुर्बानी खुद को जिंदा रखती है।

जिसे बॉलीवुड ने बताया शैतान की गुफा, जिसे दुष्ट मुगलों ने खंडहर बनाया, अब होगा उस 600 वर्ष पुराने मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार

जम्मू कश्मीर में 600 वर्ष पुराने मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, ये वही मंदिर हैं जिसे दुष्ट मुगल आक्रांता सिकंदर शाह मिरी ने तोड़ा था और बॉलीवुड ने कई मंदिर को शैतान की गुफा के रूप में दिखाया। लेकिन अब धीरे धीरे सनातन संस्कृति को इसका सम्मान मिलने लगा है और उसी कड़ी में जल्द इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी जगा। सम्राट ललितादित्य मुक्तपद ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ललितादित्य मुक्तपद करकोटा वंश के राजा थे। उन्होंने सातवीं शताब्दी में शासन किया था। राजतरंगिणी में उनकी महिमा का वर्णन है। हाल ही में अनंतनाग स्थित राम मंदिर में अयोध्या से आए कलश को स्थापित किया गया था। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी, 2024 को यहाँ हिन्दू कार्यकर्ताओं ने आकर पूजा-अर्चना भी की थी। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, भगवा ध्वज लहराया गया और मंदिर की परिक्रमा की गई।

जम्मू कश्मीर में स्थित प्राचीन मार्तण्ड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सोमवार (1 अप्रैल, 2024) को इस सम्बन्ध में एक उच्च-स्तरीय बैठक भी बुलाई है। इसमें अनंतनाग स्थित प्राचीन मार्तण्ड सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार पर भी फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक अधिसूचना में लिखा है, "संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें कश्मीर के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार/संरक्षण/सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी।"

साथ ही इस अधिसूचना में बड़ी जानकारी दी गई है कि मार्तण्ड सूर्य मंदिर परिसर में इसके निर्माता सम्राट ललितादित्य मुक्तपद की प्रतिमा की स्थापना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट स्थित अपने चैंबर में प्रधान सचिव ने ये बैठक बुलाई है। बता दें कि महाराज ललितादित्य मुक्तपद ने ही मार्तण्ड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सुल्तान सिकंदर शाह मीरी, जिसे मूर्तियाँ तोड़ने की आदत के कारण बुतशिकन भी कहा गया, उसने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। ललितादित्य मुक्तपद करकोटा वंश के राजा थे। उन्होंने सातवीं शताब्दी में शासन किया था। राजतरंगिणी में उनकी महिमा का वर्णन है। हाल ही में अनंतनाग स्थित राम मंदिर में अयोध्या से आए कलश को स्थापित किया गया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के भक्तगण भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मार्तण्ड सूर्य मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर चुके हैं। 'हैदर' फिल्म के जरिए इस मंदिर को बदनाम किया गया था और इसे 'शैतान की गुफा' बताया गया था।

ओडिशा के कोणार्क और गुजरात के मोढेरा की तरह कश्मीर का मार्तण्ड सूर्य मंदिर भी भगवान सूर्य को समर्पित भव्य हिन्दू मंदिरों में से एक है, जिसका वैभव प्राचीन काल में बहुत बड़ा हुआ करता था। फ़लिहाल ये ASI के संरक्षण में है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी, 2024 को यहाँ हिन्दू कार्यकर्ताओं ने आकर पूजा-अर्चना भी की थी। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, भगवा ध्वज लहराया गया और मंदिर की परिक्रमा की गई।

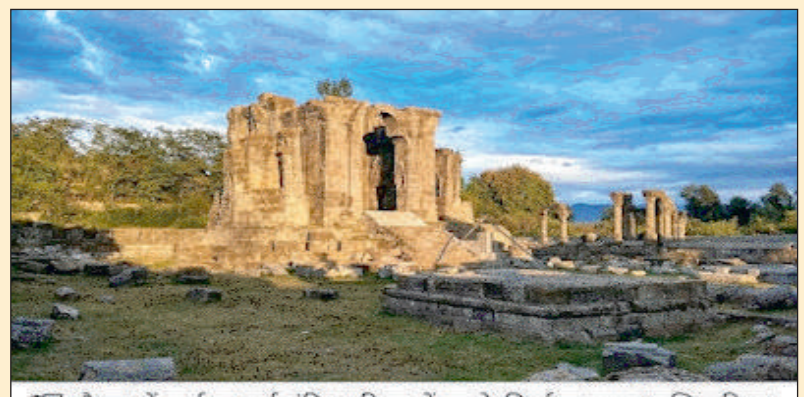

बैठक में मार्तण्ड सूर्य मंदिर परिसर में इसके निर्माता सम्राट ललितादित्य मुक्तपद की प्रतिमा की स्थापना को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

तिहाड़ के अंदर केजरीवाल, बाहर समर्थकों का बवाल

24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे मुख्यमंत्री

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ ले जाया गया है। उन्हें तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। वहीं जैसे ही यह फैसला आया वैसे ही समर्थकों की भीड़ तिहाड़ के सामने जुटने लगी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की। इस दौरान तिहाड़ के सामने भीषण जाम लग गया।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ ले जाया गया है। उन्हें तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। वह यहां अकेले रहेंगे और 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे।

बता दें, केजरीवाल की ईडी कस्टडी की अवधि सोमवार को खत्म हो गई थी। कोर्ट में मामले पर बहस हुई और उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जैसे ही यह फैसला आया, वैसे ही समर्थकों की भीड़ तिहाड़ के सामने जुटने लगी। इसके बाद उन्हें दोपहर 4 बजे कोर्ट से बाहर निकालकर जेल ले जाया गया।

भीड़ जुटने से लगा जाम

वहीं तिहाड़ के बाहर आप के समर्थक भारी संख्या में जुटे थे। एएनआई के वीडियो में सभी समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जेल के सामने से हटाया। इस कारण वहां पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ी।

महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी

वहीं प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाएं सड़कों पर बैठकर जमकर नारेबाजी कर रही थी। पुलिसकर्मियों ने सभी को वहां से घसीटकर ले गए। सभी केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। कई महिलाओं को चोट लगने की बात कही जा रही है।

इन चीजों की कोर्ट से मांगी अनुमति

बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में तीन किताबें पढ़ने की इच्छा जताई है। इसमें भगवद्गीता, रामायण और नीरजा तिवारी की लिखी पुस्तक 'हाऊ प्राइमिनिटर्स डिसाइड' शामिल हैं। वहीं उन्होंने धार्मिक लॉकेट की भी डिमांड की है। इसके साथ ही उन्होंने स्पेशल डाइट और दवाएं भी मांगी है।

तीसरी बार तिहाड़ पहुंचे दिल्ली के सीएम, जेल संख्या 2 में रहेंगे; जानें कब-कब सलाखों के पीछे पहुंचे थे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। इसी जेल में राज्यसभा सांसद संजय सिंह रह रहे थे। उन्हें अब जेल नंबर 5 में भेजा जाएगा। आबकारी से जुड़े नेताओं को एक जेल में रखने के बजाय अलग-अलग जेलों में रखे जाने का चलन है। केजरीवाल को दिल्ली पुलिस कोर्ट से बाहर निकालकर तिहाड़ ले जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले वह करीब 9 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहे। अब उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। इससे पहले इसी जेल में राज्यसभा सांसद संजय सिंह रह रहे थे। उन्हें अब जेल नंबर 5 में भेजा जाएगा। आबकारी से जुड़े नेताओं को एक जेल में रखने के बजाय अलग-अलग जेलों में रखे जाने का चलन है। केजरीवाल को जेल में लाने की तैयारी चल रही है। वे शाम 5 बजे तिहाड़ पहुंच जाएंगे। अभी जेल मुख्यालय में डीजी, डीआईजी और एआईजी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री रहते पहली बार तिहाड़ में केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार तिहाड़ पहुंचे। इससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान उन्हें तिहाड़ लाया गया था। इसके बाद उन्हें अवमानना के एक मामले में तिहाड़ जाना पड़ा था। तीसरी बार अब दिल्ली शराब घोटाला मामले के सिलसिले में केजरीवाल को तिहाड़ जाना पड़ा है। हालांकि वह साल 2017 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में तिहाड़ पहुंचे थे। कैदी के रूप में वह तीसरी बार जेल पहुंचेंगे।

केजरीवाल ने लिए दो मंत्रियों के नाम, ED ने कोर्ट में किया दावा

आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के दो और मंत्री फंस सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन मंत्रियों का नाम लिया है। ये मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज हैं। ईडी की तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने बयान में कहा कि विजय नायर उनके बजाए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था।

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के दो और मंत्री फंस सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन मंत्रियों का नाम लिया है। ये मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज हैं।

ईडी की तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने बयान में कहा कि विजय नायर उनके बजाए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड् भी नहीं दिया है। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया।

केजरीवाल की आज कोर्ट में हुई पेशी

आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उससे पहले वह 9 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहे थे। उन्हें 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल-2 में रखा जाएगा।

जेल में ये किताबें पढ़ना चाहते हैं दिल्ली सीएम

सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से ईडी की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के दौरान तीन किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी है। दिल्ली सीएम ने जिन तीन किताबों को पढ़ने की अनुमति मांगी है, उनमें भगवद्गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की 'हाऊ प्राइमिनिटर्स डिसाइड' शामिल है।

तिहाड़ के सेल में अकेले रखे गए हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल, नहीं मिलेगी कोई स्पेशल सुविधा

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के जेल संख्या दो में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से उन्हें बैरक के बजाय सेल में रखा गया है। बैरक बड़े हॉल को कहते हैं जिसमें 25-30 कैदी रखे जा सकते हैं जबकि सेल में न्यूनतम एक व अधिकतम पांच कैदी साथ रह सकते हैं।

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के जेल संख्या दो में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से उन्हें बैरक के बजाय सेल में रखा गया है।

बैरक बड़े हॉल को कहते हैं, जिसमें 25-30 कैदी रखे जा सकते हैं, जबकि सेल में न्यूनतम एक व अधिकतम पांच कैदी साथ रह सकते हैं। सेल में फिलहाल केजरीवाल अकेले हैं।

मुख्यमंत्री को कोई विशेष सुविधा नहीं

जेल प्रशासन के अनुसार, कोर्ट के निर्देश के अलावा मुख्यमंत्री को यहां कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। जेल नियमावली के अनुसार एक कैदी को मिलने वाली सुविधाएं ही केजरीवाल को मिलेंगी। पुलिस की तीसरी बटालियन की सुरक्षा में मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल वैन से शाम 4:03 बजे गेट संख्या दो से जेल परिसर में दाखिल हुए।

उन्हें जेल संख्या दो ले जाया गया। यहां ड्योढ़ी में कैदी के रूप में उनसे जुड़ी तमाम जानकारी रजिस्टर व पीएमएस (प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम) में दर्ज करने व स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें जेल परिसर में दाखिल कराया गया। यहां से मुख्यमंत्री को सीधे उनको सेल में ले जाया गया।

जेल महानिदेशक खुद करेंगे मॉनिटरिंग

जेल प्रशासन के अनुसार, मुख्यमंत्री के सेल के आसपास तीन स्तर की सुरक्षा है। पहले स्तर पर सीसीटीवी कैमरे का पहरा है। सेल व आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी जेल के महानिदेशक खुद मॉनिटरिंग करेंगे। सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर 24 घंटे यहां तैनात रहेगा। इससे आगे जेल की क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) टीम भी निगरानी रहेगी।

जेल संख्या दो में अभी क्षमता से अधिक कैदी

जेल संख्या दो में 455 कैदियों को रखने की क्षमता है। इस जेल में अमूमन सजायाफ्ता कैदियों को जगह दी जाती है। वजह यह है कि इस जेल में तिहाड़ की बड़ी फैक्ट्रियां हैं। सजायाफ्ता कैदियों के लिए इन फैक्ट्रियों में काम की कमी नहीं होती है। वर्तमान में यहां 635 कैदी हैं।

इनमें करीब 600 सजायाफ्ता हैं। कुछ दिन पूर्व तक इस जेल में आबकारी नीति घोटाले में ही आप नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बंद थे। फिलहाल उन्हें स्थानांतरित करके जेल संख्या पांच में भेज दिया गया है।

कौन नेता किस जेल में है बंद

नाम-	*जेल संख्या*
अरविंद केजरीवाल	- दो
मनीष सिसोदिया	- एक
संजय सिह	- पांच
के. कविता (बीआरएस)	- छह

तिहाड़ जेल पहुंचे आप के टॉप-4 नेता, जानिए कौन-कौन सी सेल में बंद हैं केजरीवाल-सिसोदिया समेत दूसरे नेता

परिवहन विशेष न्यूज

आम आदमी पार्टी (AAP) के टॉप चार नेता तिहाड़ पहुंच चुके हैं। एक अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था वो किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए थे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के टॉप चार नेता तिहाड़ पहुंच चुके हैं। एक अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, वो किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए थे।

ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो 9 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहे फिर, उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तिहाड़ जेल नंबर-2 में रहेंगे।

ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति (DELHI EXCISE POLICY 2021-22) में बदलाव के बदले केजरीवाल ने दक्षिण समूह के शराब व्यापारियों से 100 करोड़ रुपये के रिश्वत की मांग की थी और उक्त धनराशि का इस्तेमाल गोवा व पंजाब विधानसभा में खर्च किया गया था।

यहां हैं सिसोदिया और संजय सिंह

तिहाड़ जेल में आबकारी मामले में संजय सिंह जेल नंबर-2 में बंद थे। अरविंद केजरीवाल को अब जेल नंबर-2 में रखने के बाद उन्हें जेल नंबर-5 में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं, जेल नंबर 4 में विजय नायर बंद है। सत्येंद्र जैन जेल संख्या-7 में हैं, लेकिन वह पहले ही किसी और मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।

सिसोदिया 26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में सिसोदिया को कई घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने 28 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्हें 9 मार्च को तिहाड़ में आठ घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

सत्येंद्र जैन को इस मामले में किया था गिरफ्तार

ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था।

चार अक्टूबर को संजय सिंह हुए थे गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी की गई थी।

वाहन, टेंट, पंखा-बत्ती, खाना-पीना, फूल, फोटो के तय किए दाम

खुशी में ढोल पीटवाना हो या नेताजी का कटआउट लगाना, सबकी दरें हुई तय

परिवहन विशेष न्यूज

चुनाव आयोग द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी 1760 रुपये प्रतिदिन की दर से सबसे महंगी गाड़ी किराए पर ले सकता है। कुर्सी की लड़ाई में साधारण कुर्सी के लिए 16.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर ले सकते हैं और खुशी में ढोल पीटवाना हो तो तीन घंटे के लिए 500 रुपये अधिकत्तम खर्च किए जा सकेंगे।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली संसदीय सीट के प्रत्याशियों के खर्च करने के लिए हर चीज की कीमत तय कर दी है। प्रत्याशी की सभा से लेकर कार्यकर्ताओं पर खर्च का हिसाब आयोग द्वारा तय की गई राशि के अनुसार लगाया जाएगा। सात पन्ने की इस सूची में वाहन, टेंट, पंखा-बत्ती, खाना-पीना, फूल, फोटो आदि तमाम चीजों की दर तय की गई है। यानी 95 लाख अधिकतम खर्च करने की सीमा में प्रत्याशी किसपर कितना खर्च करें, यह रोडमैप दिया गया है।

जारी लिस्ट के मुताबिक, कोई भी प्रत्याशी 1760 रुपये प्रतिदिन की दर से सबसे महंगी गाड़ी किराए पर ले सकता है। लेकिन, बस या ट्रेवलर के लिए छह हजार तक भी खर्च कर सकता है। कुर्सी की लड़ाई में साधारण कुर्सी के लिए 16.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराये पर ले सकते हैं और खुशी में ढोल पीटवाना हो तो तीन घंटे के लिए 500 रुपये अधिकत्तम खर्च किए जा सकेंगे।

नेताजी को कटआउट लगाने के लिए भी दरें तय

नेताजी को कटआउट लगाने की इच्छा हो तो 50 रुपये प्रति वर्ग फीट तक खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही बड़ी माला के लिए 600 व छोटी माला के लिए 25 रुपये चुका पाएंगे। इसी प्रकार टेंट या फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कराने की भी कीमत तय की गई है। फोटोग्राफर को आठ घंटे की ड्यूटी के लिए करीब 13 सौ और वीडियो कवरेज के लिए 3025 रुपये अधिकतम दे सकेंगे।

मुंह मीठा कराने के लिए सूची में रसगुल्ला और जलेबी

इसके अलावा, चाय, नाश्ता, खाना सबका दाम तय किया गया है। दस प्रकार के प्लेट के रेट तय किए गए हैं। इसमें शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। जनता आहार 39 रुपये तो अधिकतम 190 रुपये में मांसाहारी भोजन कराने की छूट होगी। पांच के समोसे और 10 के पकौड़े ही लेने होंगे। मुंह मीठा कराना हो तो सूची में रसगुल्ला, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, हलवा भी है।

कैसे तय होती है कीमतें

नई दिल्ली निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, सभी चीजों की कीमत तय करने से पहले सभी दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक की जाती है। इस संबंध में चर्चा और सहमति के बाद पिछले चुनाव से हो रहे चुनाव के बीच महंगाई कितनी बढ़ी उसका ध्यान रखा जाता है। उसी अनुसार रेट तय किया जाता है।

अधिकारी ने बताया कि जैसे एक समोसे की कीमत पांच रुपये तय की गई है, लेकिन बाजार में कीमत दस रुपये है। अगर प्रत्याशी इसे पांच हजार पीस लेगा तो यह पांच का मिल जाएगा, साइज भी उसी हिसाब से बदलवाया जा सकता है। इसलिए इसे थोक रेट के हिसाब से तय किया जाता है।

खाने पीने की चीजों के तय दाम

व्यंजन	*कीमत (रुपये में)*
छोले कुलचे	15 प्रति प्लेट
पकौड़े (मिक्स)	19 प्रति प्लेट
सैंडविच	15 प्रति पीस
चाय	7 प्रति कप
पूरी सब्जी	19 प्रति प्लेट
समोसा	5
ब्रेड पकौड़ा	9.50 प्रति पीस
शिकंजी	20 प्रति गिलास
लस्सी	30 प्रति गिलास
रसगुल्ला	20 प्रति पीस
इमरती	40 प्रति सौ ग्राम
जलेबी	35 प्रति सौ ग्राम
रसमलाई	30 प्रति पीस

लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चों पर रहेगी पल-पल नजर, चाय से लेकर कुर्सी के पैसे भी होंगे तय

लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर पल-पल की नजर रखने के लिए प्रशासन ने 40 अधिकारियों व कर्मचारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। ये कर्मचारी दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट पर प्रत्याशियों की ओर से प्रचार में होने वाले खर्च को रजिस्टर में दर्ज करेंगे। संसदीय क्षेत्र में आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में तीन-तीन कर्मचारियों की टीम नियुक्त की गई है।

दक्षिणी दिल्ली। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर पल-पल की नजर रखने के लिए प्रशासन ने 40 अधिकारियों व कर्मचारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। ये कर्मचारी दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट पर प्रत्याशियों की ओर से प्रचार में होने वाले खर्च को रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

संसदीय क्षेत्र में आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में तीन-तीन कर्मचारियों की टीम नियुक्त की गई है। इस बार चुनाव में एक प्रत्याशी को 95 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है। प्रत्येक विधानसभा में गठित तीन सदस्यीय टीम में एक वित्त लेखाधिकारी भी शामिल किया गया है, जिन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके साथ ही 10 अधिकारियों की एक अलग टीम बनाई गई हैं, जिनमें से तीन पर्यवेक्षक हैं। जो मुख्यालय में रहेंगे। ये 10 अधिकारी टीम की ओर से दिया ब्योरा देखेंगे और प्रत्याशियों से मिलने वाले खर्च की जानकारी से मिलान करेंगे।

ब्योरे का मिलान नहीं होने पर जारी होगा नोटिस

टीम और प्रत्याशी की ओर से दिए गए ब्योरे में अगर मिलान नहीं होता है, तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सही रिपोर्ट देने के लिए कहा जाएगा।

नामांकन शुरू होते टीम हो जाएगी सक्रिय

दक्षिणी दिल्ली सीट पर नामांकन शुरू होते ही खर्च पर निगरानी रखने वाली टीम भी सक्रिय हो जाएगी। टीम प्रत्याशियों की बैठक, रैली, सभा, कार्यालय, नुक्कड़ सभा और प्रत्याशियों का भ्रमण पर नजर रखेगी।

चाय से लेकर सभा तक खर्च सीमा तय की जाएगी

प्रशासन चाय से लेकर जनसभा तक होने वाले खर्च को निर्धारित करेगा। इसके लिए सूची तैयार की जा रही है। जनसभा में आने वाले हेलीकॉप्टर, हेलीपैड का भी खर्चा जोड़ा जाएगा। इसके लिए खर्च के मानक तय किए जाएंगे। प्रशासन नामांकन से पहले खाने-पीने, कुर्सी, पंडाल आदि के खर्च की सूची जारी कर देगा।

वित्त अधिकारियों को प्रत्याशियों के व्यय पर नजर रखने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लगाई गई हैं, जो खर्च का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा, नियम न मानने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पालतू कुत्तों को लेकर आज एक अप्रैल से नियम बदल गया है। अब पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को एक हजार रुपये देने होंगे। इससे पहले पालतू कुत्ते का पंजीयन कराने के लिए 200 रुपये देने पड़ते थे। साथ ही नियमों को न मानने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

गाजियाबाद। एक अप्रैल से पालतू कुत्तों को पंजीकरण शुल्क बढ़ गया है। सोमवार से पालतू कुत्ते का पंजीयन कराने के लिए 200 रुपये की बजाय लोगों को एक हजार रुपये देने होंगे। कुत्ता पालने के लिए बनाई गई नई नीति के नियमों का पालन न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

कितना है कुत्तों का पंजीकरण शुल्क?

इसके अलावा निगम ने कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री व प्रजनन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया है। निगम के उप-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार सिंह ने बताया कि नई नीति में कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 200 से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। वहीं हर साल किए जाने वाले नवीनीकरण शुल्क को भी 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

कितनी है पालतू कुत्तों की संख्या?

मालूम हो कि निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों की संख्या करीब 20 हजार से ज्यादा होने का अनुमान है। मगर अभी तक निगम में सिर्फ छह हजार कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। बिना पंजीकरण के कुत्ता पालने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने व प्रजनन पर भी 10 हजार रुपये ही जुर्माना लगेगा, जो लोग प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पहले से पाल रहे हैं उन्हें उन कुत्तों की अनिवार्य रूप से नसबंदी करानी होगी। नसबंदी कराने के बाद प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से निगम कार्यालय में जमा कराना होगा।

कुत्तों की इन नस्लों पर प्रतिबंध

निगम अधिकारियों की माने तो कुत्तों की पिटबुल, टेरियर, राटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडाग, बोएरबोएल, कांगल, मध्य एशियाइ शेफर्ड डाग, दक्षिण रूसी शेफर्ड, कोकेशियान शेफर्ड डाग, सप्लीनिनैक, जापानी टोसा, मास्टिफ्स आदि कुल 23 नस्ल पर प्रतिबंध है।

वसुंधरा में 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे तीन बच्चे, बिगड़ी तबीयत

गाजियाबाद में लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला वसुंधरा सेक्टर 11 का है। जहां रविवार शाम को लिफ्ट खराब होने से उसमें तीन बच्चे 45 मिनट तक फंसे रहे। बच्चों के शोर मचाने पर लोगों ने लिफ्ट तोड़कर उन्हें बचाया। तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने लिफ्ट का नियमित मेंटेनेंस नहीं करने का आरोप लगाया है।

परिवहन विशेष न्यूज

साहिबाबाद। वसुंधरा सेक्टर 11 के द्रोणागिरी अपार्टमेंट में टावर की रविवार शाम को लिफ्ट खराब होने से उसमें तीन बच्चे 45 मिनट तक फंसे रहे। बच्चों के शोर मचाने पर लोगों ने लिफ्ट तोड़कर उन्हें बचाया। तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने घटिया दर्जे की लिफ्ट लगाने और नियमित मेंटेनेंस नहीं करने का आरोप लगाया है।

भूतल से लिफ्ट में सवार हुए थे तीनों

अपार्टमेंट के अर्क शंकर, कौस्तव बंसल, युवराज सिंह तीनों बच्चे रविवार शाम को खेलने गए थे। तीनों की उम्र लगभग 11 से 12 के बीच हैं। शाम करीब छह बजे वह खेलकर अपने फ्लैट में जा रहे थे। भूतल से तीनों लिफ्ट में सवार हो गए।

लिफ्ट चौथे और पांचवें तल के बीच फंस गई। बच्चों ने काफी शोर मचाया लेकिन किसी को सुनवाई नहीं दिया। तीनों बच्चे अंदर रोने लगे। इनमें अर्क शंकर ने रोते हुए अपने दोनों दोस्तों की काउंसलिंग की और हिम्मत बनाए रखने की बात कही। कुछ देर बाद ही अपार्टमेंट की बिजली आपूर्ति रुक गई।

इससे लिफ्ट में अंधेरा हो गया। इससे बच्चे अधिक डर गए। तभी चौथे तल पर लिफ्ट के पास पहुंचे एक व्यक्ति को बच्चों की आवाज सुनाई दी। उन्हें अहसास हुआ कि लिफ्ट में बच्चे हैं। सोसायटी के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे।

लोगों ने राड और लकड़ी की मदद से लिफ्ट को तोड़ा। इसके बाद बच्चों को बाहर निकाला। इनमें युवराज को चोट भी लगी है। बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया। अर्क शंकर के पिता अमित शंकर ने बताया कि सोसायटी में बहुत ही घटिया दर्जे की लिफ्ट लगाई गई हैं। उनका नियमित रूप से मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। लोग अपने खर्चे से ही अपार्टमेंट की देखरेख करते हैं।

अभिभावकों में रोष

लिफ्ट की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है। वह सभी टावरों की लिफ्ट बदलवाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी अमित ने बताया कि आए दिन लिफ्ट खराब हो जाती हैं। बच्चे सहमे हुए हैं। यदि लिफ्टों को नहीं बदला जाता है तो आने वाले समय भी हादसे की आशंका है।

सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं की मदद

अमित शंकर का आरोप है कि मेंटेनेंस समिति के सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को रेस्क्यू कराने में कोई मदद नहीं की। सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट की चाबी तलाश करने में लगा रहा। मेंटेनेंस के नाम पर खानापूरी की जाती है। सुरक्षा के मानक भी पूरे नहीं है। जबकि यह सोसायटी में लोगों को 2020-22 से कब्जा मिलना शुरू हुआ था। यह ज्यादा पुरानी सोसायटी नहीं है।

लिफ्ट लगाने के ये हैं मानक

लिफ्ट में कैमरा होना चाहिए
आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस लगी हो
लिफ्ट का अलार्म सिक्योरिटी रूम से जुड़ा हो
इंटरकाम की सुविधा होनी चाहिए
लिफ्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए
लिफ्ट में अग्निशमन यंत्र भी लगा हो

लिफ्ट खराब होने की चूक

समय पर मेंटेनेंस नहीं होना
लिफ्ट की क्वालिटी बेकार होना
लिफ्ट में वजन से ज्यादा लोगों का रहना
लिफ्ट को उपयोग करना नहीं आना
लिफ्ट में गार्ड का न होना
मेंटेनेंस नहीं करने का आरोप गलत है। इस तरह का यह पहला मामला हुआ है। लिफ्टों का नियमित मेंटेनेंस किया जाता है। यह मशीन है। कभी भी खराब हो सकती है।

– विपिन दीक्षित, मेंटेनेंस सुपरवाइजर

इंदिरापुरम में महिला से चेन और बैंककर्मी से लूटा मोबाइल, वीडियो आया सामने

गाजियाबाद में चोरों के हौंसले बुलंद हैं। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से चेन और बैंक कर्मचारी से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना ने चुनाव में कड़ी सुरक्षा के दावों के बीच हो रही लूट ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

साहिबाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर 11 में महिला से चेन और अभय खंड में बैंककर्मी से बाइक सवार बदमाश ने मोबाइल लूट लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दोनों पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चुनाव में कड़ी सुरक्षा के दावों के बीच हो रही लूट ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

गौड़ ग्रीन एवेन्यू के आलोक रंजन बैंक प्रबंधक हैं। रविवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर से बाहर गए थे। सड़क किनारे पैदल चल रहे थे। तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने उनसे मोबाइल लूट लिया। उन्होंने शोर मचाते हुए काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गया।

बाजार जा रही थीं सरोज कुमारी

घटना सोसायटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं वसुंधरा सेक्टर 11 की सरोज कुमारी पति और रिश्तेदार के साथ पैदल बाजार जा रही थीं।

सामने से आए बाइक सवार बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन लूट ली। पीड़िता ने कोतवाली पहुंच कर तहरीर दी। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फुटेज के आधार पर आरोपित की तलाश में टीम लगी हैं।

स्नेक वेनम केस में ओडिशा से आया लेटर, दूसरे देशों के सांपों के अनुमति पत्र का मिलान करेगी पुलिस

परिवहन विशेष न्यूज

बिग बास ओटीटी सीजन दो के विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव और मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया द्वारा 32 बोर के गाने की शूट के दौरान दूसरे देशों के सांपों के इस्तेमाल के मामले में पुलिस को ओडिशा के जिला भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन से जवाब मिल गया है। पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन को पत्र लिखा था। इसमें सांपों की अनुमति के बारे में पूछा गया था।

गुरुग्राम। बिग बास ओटीटी सीजन दो के विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव और मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया द्वारा 32 बोर के गाने की शूट के दौरान दूसरे देशों के सांपों के इस्तेमाल के मामले में पुलिस को ओडिशा के जिला भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन से जवाब मिल गया है।

पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन को पत्र लिखा था। इसमें सांपों की अनुमति के बारे में पूछा गया था। गाने के लिए सांप उपलब्ध कराने वाले दिल्ली के हार्दिक ने अनुमति होने का पत्र सौंपा था। अब भुवनेश्वर से मिले जवाब का पुलिस हार्दिक के दस्तावेज से मिलान करेगी।

PFA ने की थी पुलिस से शिकायत

पिछले साल अक्टूबर में पीपल फार एनिमल (पीएफए) की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद गायक राहुल फाजिलपुरिया को जांच शामिल किया गया था।

फाजिलपुरिया ने जांच में दिल्ली के झाड़ौदा निवासी हार्दिक का नाम देते हुए बताया था कि उसके पास दूसरे देश के सांप (एजोटिक सांप) और छिपकली (इगुआना) रखने की अनुमति है।

इस पर पुलिस ने हार्दिक को जांच शामिल करते हुए अनुमति पत्र मांगे थे। हार्दिक की तरफ से दिखाए गए पत्र में ओडिशा के भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन से अनुमति थी। इसके बाद पुलिस ने भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन को अनुमति पत्र को सत्यापित करने के लिए पत्र लिखा था।

हार्दिक की तरफ से तीन सांपों और एक छिपकली के बारे में दस्तावेज पुलिस को दिखाए गए थे। उसमें मैक्सिकन ब्लैक किंग प्रजाति का सांप, रेड टेल सांप व कार्न सांप और कामन छिपकली (इगुआना) के बारे में लिखा था।इस मामले में एल्विश और राहुल फाजिलपुरिया के विरुद्ध अदालत के आदेश पर वन्यजीव के साथ क्रूरता और अभद्र भाषा को लेकर बादशाहपुर थाने में शनिवार को केस भी दर्ज किया गया है।

कहां पाए जाते हैं सांप

1.मैक्सिकन ब्लैक किंग सांपः अमेरिका के ऐरिजोना से मैक्सिको के बीच में पाया जाता है।

2. रेड टेल सांपः कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।

3. कार्न सांपः अमेरिका के जर्सी और फ्लोरिडा के बीच पाया जाता है।

4. कामन इगुआना (छिपकली) : मैक्सिको से ब्राजील के बीच में पाई जाती है।

मामले में गहनता से जांच की जा रही है। मुख्य वन्यजीव वार्डन भुवनेश्वर से पत्र का जवाब आ गया है। हार्दिक की तरफ से दिए गए दस्तावेज और भुवनेश्वर से आए सत्यापन के पत्र का मिलान किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

– वरुण दहिया, एसीपी क्राइम

नोएडा में लोग और पुलिस हरकत में, आसमान में छाने लगा काला धुआं; सांस लेने में होने लगी दिक्कतें

नोएडा के कोतवाली सेक्टर-126 प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-128 स्थित निर्माणाधीन कल्पतरू बिल्डिंग में रखी थर्माकोल में सोमवार शाम अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। देखते ही देखते थर्माकोल से निकलने वाला धुंआ आसमान में छा गया। इससे लोगों को सांस लेने में भी समस्या हुई।

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-126 के सेक्टर 128 स्थित एक बिल्डिंग में रखी थर्माकोल में भीषण आग लग गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-128 स्थित निर्माणाधीन कल्पतरू बिल्डिंग में रखी थर्माकोल में सोमवार शाम अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग में कार्य कर करने वाले कामगारों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते थर्माकोल से निकलने वाला धुंआ आसमान में छा गया। कई किलोमीटर से आसमान में धुंआ को देखा जा सकता था। इससे लोगों को सांस लेने में भी समस्या हुई। **घटना में कोई जनहानि नहीं :** दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं थर्माकोल में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है।

नोएडा में सपा के बाद गाजियाबाद में बसपा ने बदला अपना प्रत्याशी, अब मायावती ने इन पर जताया भरोसा

बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने गाजियाबाद से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इससे पहले बसपा ने अंशय कालरा को टिकट दिया था लेकिन सोमवार को पार्टी ने इस सीट से अंशय की जगह नंद किशोर पुंढीर को उतार दिया। नंद किशोर पुंढीर की टक्कर अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा से होगी।

गाजियाबाद। बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने गाजियाबाद से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इससे पहले बसपा ने अंशय कालरा को टिकट दिया था। लेकिन सोमवार को पार्टी ने इस सीट से अंशय की जगह नंद किशोर पुंढीर को उतार दिया। जिला अध्यक्ष दया राम सैन ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर में नामांकन पत्र खरीदा गया है।

नंद किशोर पुंढीर की टक्कर अब भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग और कांग्रेस की डाली शर्मा से होगी। बता दें, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 7 अप्रैल को गाजियाबाद में रैली को संबोधित करेंगे।

सपा ने नोएडा से बदले थे प्रत्याशी

बता दें, इससे पहले गौतमबुद्ध नगर सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी बदला था। पहले यहां से सपा ने राहुल अवाना को टिकट दिया था, लेकिन बाद में विरोध होने पर महेंद्र नागर के नाम पर अंतिम मुहर लगी है। इस सीट से अब डॉ. महेंद्र नागर ही सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

राजनीति में बदल रहे नैतिकता के मायने

दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उस पर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सवालों की परिधि में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।

सुरेश हिंदुस्तानी

केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठना तो उसी समय प्रारंभ हो गए थे, जब उनका पहला मंत्री जेल में गया। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। राजनीतिक शुचिता लाने का दम दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगने केवल राजनीतिक विद्वेष नहीं हो सकता।

भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो आज भी नैतिकता के आदर्श हैं। लेकिन आज की राजनीति को देखकर ऐसा लगने लगा है कि नैतिकता की राजनीति दूसरा तो अवश्य करें, पर ज़ब स्वयं को नैतिकता की कसौटी पर परखने की बारी आए तब नैतिकता के मायनों को बदल दिया जाता है। भारतीय राजनीति में राजनेताओं पर आरोप लगने पर कई लोगों ने अपने पद को त्याग दिया था, दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को अलग राह पर ले जाने का उदाहरण पेश किया है, हालांकि इस उदाहरण को आदर्श वादिता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। यह एक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं हैं। केजरीवाल स्वयं कहते थे कि वे राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन अब ज़ब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, तब उनसे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की आशा करना बेमानी ही कही जाएगी। यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अभी तक जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको जमानत लेने का पर्याप्त आधार नहीं मिल रहा, इसका आशय यह भी है कि सरकार की ओर से कोई न कोई गलत आचरण किया गया होगा, अन्यथा एक मुख्यमंत्री को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जाता। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी यही कहा जा रहा है, उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के संकेत पर पैसों का लेनदेन हुआ।

दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उस पर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सवालों की परिधि में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह साफ तौर पर संकेत दिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे आरोप किस हद तक सही हैं या फिर केजरीवाल अपने आपको निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। अगर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगाए गए आरोपी प्रमाणित होते हैं तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवैधानिक पद के प्रभाव का दुरुपयोग किया है।

केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठना तो उसी समय प्रारंभ हो गए थे, जब उनका पहला मंत्री जेल में गया। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। राजनीतिक शुचिता लाने का दम दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगने केवल राजनीतिक विद्वेष नहीं हो सकता।

हम यह भली भांति जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने आपको ऐसा प्रचारित किया कि एक वे ही भारतीय राजनीति के उच्चतम आदर्श हैं। लेकिन उनके आचरण पर स्वयं अण्णा हजारे ने सवाल उठाए थे, हालांकि अण्णा हजारे के सवालों को केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया। इसका तात्पर्य यही है कि अन्ना हजारे राजनीति में जिस प्रकार का पारदर्शी व्यवहार चाहते थे, वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी समाजसेवी अण्णा हजारे की ओर से साफ सुथरी टिप्पणी आई है, जिसमें अण्णा हजारे ने शराब पर नीति बनाने से रोका था। अण्णा हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का परिणाम बताया। आज दिल्ली का शराब घोटाला यही चरितार्थ करते हुए लग रहा है कि शराब किसी भी संस्था या व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। यह बात केजरीवाल पर लागू होती है या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन जब आग लगती है तब ही धुंआ उठता है और इस धुंए का कालिमा किस किस के शक्ल को बिगाड़ने का काम करेगी, यह समय के गर्भ में है।

केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठना तो उसी समय प्रारंभ हो गए थे, जब उनका पहला मंत्री जेल में गया। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। राजनीतिक शुचिता लाने का दम दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगने केवल राजनीतिक विद्वेष नहीं हो सकता। अगर यह कार्यवाही राजनीतिक होती तो स्वाभाविक रूप से इन सभी को जमानत भी मिल जाती। जमानत नहीं मिलने से यह आशंका प्रबल हो जाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता भी केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ही विरोध कर रहे हैं, कोई भी यह नहीं कह रहा कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ या फिर गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगाया। यह बात सही है कि राजनीतिक तौर पर तर्क तो कई दिए जा सकते हैं, लेकिन इन तर्कों का आधार क्या है? यह कोई नहीं बता पाता।

भारत की राजनीति में इसे विसंगति ही माना जाएगा कि कोई अपराधी और उसके समर्थक उसे ऐसे नायक के रूप में प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं, जैसे वह समाज के लिए आदर्श बन गया हो। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें नेता जमानत पर बाहर आकर राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं। क्या वास्तव में ऐसे राजनेता देश के राजनीतिक वातावरण को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। कदाचित नहीं। क्योंकि आज के राजनीतिक माहौल में राजनेता जैसा अपने आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसा सिद्धांततः होता नहीं है। उनके क्रियाकलाप केवल और केवल भ्रमित करने वाली राजनीति करने की ही होती है। देश में एक समय यह आम धारणा बन चुकी थी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश की नियति बन चुकी है, लेकिन पिछले दस साल में इस धारणा को बदलने की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। यह सुगबुगाहट कई राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आ रही। ऐसे कई राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार के दोषी सिद्ध हो चुके हैं और देश की राजनीति को सुधारने की कवायद कर रहे हैं। अब सवाल यह भी आता है कि क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने का साहस दिखा सकते हैं। इसका उत्तर नहीं ही होगा, लेकिन वे फिर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारत में साफ सुथरी राजनीति के क्या यही मायने हैं? क्या ऐसे नेता राजनीति को सही दिशा दे सकते हैं, इसका उत्तर हमें स्वयं तलाश करना होगा? ऐसे ही दिल्ली सरकार के घोटाला में होता हुआ लग रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा कि गोवा में 45 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से दिए गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही साफ सुथरी राजनीति के मायने हैं? तर्क कुछ भी हों, परन्तु अब ऐसी राजनीति से देश को अलग करने का समय आ गया है।

टोयोटा Taisor का Teaser हुआ जारी, तीन अप्रैल को होगी पेश

जापानी कार निर्माता Toyota की ओर से भारतीय बाजार में कई कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से जल द आने वाली SUV Taisor का Teaser जारी कर दिया गया है। कंपनी की ओर से जारी किए गए टीजर में किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ ही इसे कब तक पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जापान की प्रमुख वाहन निर्माता Toyota जल्द ही नई एसयूवी को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है। SUV Taisor को पेश करने से पहले कंपनी ने इसका Teaser जारी किया है। जारी किए गए टीजर में किस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही इसे कब पेश किया जाएगा। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Toyota Taisor का Teaser हुआ जारी

टोयोटा की ओर से नई एसयूवी Taisor के टीजर को जारी किया गया है। जिसमें एलईडी लाइट्स और डीआरएल के साथ ही लाल रंग और रूफ रेल की जानकारी साफतौर पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा गाड़ी में क्रोम और साइड इंडीकेटर को भी साफ देखा जा सकता है।

कैसे होंगे फीचर्स

टोयोटा की यह एसयूवी मारुति की फ्रॉन्क्स का री बैज्ड वर्जन होगी। ऐसे में इसमें फ्रॉन्क्स की तरह ही फीचर्स को दिया जाएगा। लेकिन टेजर के एक्सटीरियर और इंटीरियर में हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। सुरक्षा के तौर पर इसमें छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, रियर कैमरा, थ्री पाइंट सीट बेल्ट के साथ ही क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, की लैस एंट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 22.86 सेमी का स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले और कई फीचर्स को दिया जा सकता है।

कब होगी पेश

कंपनी की योजना इस नई एसयूवी Taisor को फिलहाल पेश करने की है। जिसके बाद कुछ महीनों में इस एसयूवी को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक इसे तीन अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे के बाद पेश किया जाएगा।

मारुति और टोयोटा की साझेदारी में आएगी नई एसयूवी

भारत में टोयोटा मोटर्स और मारुति की साझेदारी में Taisor चौथी गाड़ी होगी। इससे पहले, टोयोटा की Urban Cruier Hyryder और मारुति Grand Vitara एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी एसयूवी हैं। इसके अलावा मारुति की Ertiga एमपीवी को टोयोटा Rumion के नाम से ऑफर करती है। दोनों कंपनियों की साझेदारी होने के बाद जिस गाड़ी को सबसे पहले रीबैज्ड वर्जन के तौर पर टोयोटा ने ऑफर किया था, वह Glanza है, जो Maruti Baleno पर आधारित है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर कार बाजार बना भारत, 40 लाख के पास हुई सालाना बिक्री

नई दिल्ली। भारत पैसेंजर कार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। वर्ष 2023-24 में देश में पैसेंजर कारों की कुल बिक्री 42.3 लाख रही है। भारत ने यह स्थान जापान को हटा कर हासिल किया है। असलियत में भारत ने पिछले दो वर्षों में दुनिया के दो कार बाजारों (पहले जर्मनी और अब जापान) को बिक्री में पीछे छोड़ दिया है। अब जबकि देश की आर्थिक विकास दर लंबे समय तक 7-8 फीसद तक बने रहने की संभावना है तो भारतीय कार बाजार का दमखम और बढ़ सकता है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की रही है जिसकी भारत के कार बाजार में हिस्सेदारी बढ़ कर 42 फीसद हो गई है। गत वर्ष कंपनी की कुल बिक्री पहली बार 20 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 21.35 लाख वाहनों की रही है।

सोमवार को देश की कई बड़ी आटोमोबाइल कंपनियों ने मार्च, 2024 और वित्त वर्ष 2023-24 के बिक्री के आंकड़े जारी किये हैं जो बताता है कि भारतीय कार बाजार में किस तरह से स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हिक्लस (एसयूवी) का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। मारुति सुजुकी के एक्जीक्यूटिव समिति के नये सदस्य शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि नये कारों की कुल बिक्री में 50.6 फीसद एसयूवी रहे हैं। जबकि कभी मध्यम वर्ग के सबसे आकर्षण का केंद्र रहे हैचबैक कारों की बिक्री में 6 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। उनका कहना है कि वर्ष 2023-24 भारतीय कार उद्योग के लिए बहुत शानदार रहा है लेकिन वर्ष 2024-25 में बिक्री में एकल अंकों में ही वृद्धि होगी क्योंकि पिछले वर्ष का आधार काफी ज्यादा है।

टाटा मोटर्स की तरफ से बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में उसने कुल 5,73,495 पैसेंजर कारों की बिक्री की है जो इसके पिछले वर्ष के मुताबले छह फीसद ज्यादा है। हुंडई मोटर्स की तरफ से बताया गया है कि उसने गत वर्ष कुल 7,77,886 कारों की बिक्री की है जो कंपनी की अभी तक की सबसे बड़ी बिक्री है।

मार्च में हुई हुंडई की बल्ले-बल्ले! सालाना आधार पर दर्ज की 7 प्रतिशत की ग्रोथ

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 777876 यूनिट्स की अपनी अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 720565 यूनिट्स से 8 फीसदी ज्यादा है। मार्च में निर्यात भी 16 प्रतिशत बढ़कर 12600 यूनिट हो गया है। जबकि एक साल पहले की अवधि में यह आंकड़ा 10900 यूनिट्स का था। आइए हुंडई की सेल्स रिपोर्ट के बारे में जानते हैं।

Hyundai Motor ने मार्च 2024 में बिक्री के लिहाज से सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने इस दौरान 65,601 युनिट्स की बिक्री की है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को जारी की गई सेल्स रिपोर्ट में बताया है कि डीलरों को वाहनों की डॉमेस्टिक डिस्पैच पिछले महीने 5 प्रतिशत बढ़कर 53,001 यूनिट हो गई है, जो कि एक साल पहले की अवधि में 50,600 यूनिट थी।

सालाना आधार पर दर्ज हुई वृद्धि

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 7,77,876 इकाइयों की अपनी अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 7,20,565 यूनिट्स से 8 फीसदी ज्यादा है। मार्च में निर्यात 16 प्रतिशत बढ़कर 12,600 यूनिट हो गया है, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 10,900 यूनिट्स की बिक्री की गई थी। घरेलू बाजार में ऑटो प्रमुख ने अपने डीलरों को 6,14,721 यूनिट्स भेजीं, जो कि 8 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 5,67,546 यूनिट भेजी थीं।

बिक्री में 7 प्रतिशत दर्ज हुई बढ़ोत्तरी

वित्त वर्ष 2022-23 में 1,53,019 इकाइयों की तुलना में निर्यात 7 प्रतिशत बढ़कर 1,63,155 यूनिट हो गया है। हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 23-24 में 7.77 लाख इकाइयों की बिक्री कंपनी के उत्पाद लाइन-अप की लोकप्रियता को दिखाती है। गर्ग ने कहा कि घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में 8.3 प्रतिशत बढ़ी है। यह शुरुआत के बाद से ऑटोमेकर द्वारा दर्ज की गई सबसे अधिक बिक्री है।

हुंडई के लाइनअप में EXTER, new CRETA, CRETA N LINE, new i-20, Hyundai VENUE और VENUE N Line जैसी गाड़ियां मौजूद हैं।

Kia Seltos के दो नए वेरिएंट हुए लॉन्च, जानें क्या हैं खूबियां और कितनी है कीमत

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में Seltos SUV को ऑफर किया जाता है। Kia की ओर से इस एसयूवी के दो नए वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इन दोनों वेरिएंट्स को किस कीमत पर लाया गया है और इनमें किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Kia Seltos को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस एसयूवी के दो और वेरिएंट्स को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इन नए वेरिएंट्स में कंपनी की ओर से किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। इनको किस कीमत पर बाजार में लॉन्च किया गया है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Kia Seltos के दो नए वेरिएंट लॉन्च

साउथ कोरिया की कार कंपनी Kia की ओर से एसयूवी Seltos के दो नए वेरिएंट्स को भारत में लॉन्च किया गया है। कंपनी की ओर से HTK+ पेट्रोल IVT और HTK+ डीजल 6AT को देश में लॉन्च किया गया है। इससे पहले कंपनी की ओर से HTX वेरिएंट में पेट्रोल सीवीटी को ऑफर किया जा रहा था।

कैसे हैं फीचर्स

कंपनी की ओर से HTK+ वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ड्राइव और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, पैडल शिफ्टर्स, एलईडी कनेक्टिड टेल लैंप जैसे फीचर्स के साथ इन नए मिड वेरिएंट्स को लाया गया है। जबकि इस एसयूवी में कंपनी की ओर से 16 इंच के अलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, आठ इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर डिफॉगर, एलईडी डीआरएल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स जैसे फीचर्स को भी ऑफर किया जाता है।

कितना दमदार इंजन

कंपनी Seltos में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटिड पेट्रोल इंजन देती है। जिससे एसयूवी को 114 बीएचपी और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन से एसयूवी को 114 बीएचपी और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

कितनी है कीमत

किआ सेल्टॉस के HTK+ पेट्रोल IVT वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.40 लाख रुपये है। जबकि इसके HTK+ डीजल 6एटी वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 16.90 लाख रुपये रखी गई है।

अब बौद्धिक क्षमता की बढ़त जरूरी

डा. जयंती लाल भंडारी

हम उम्मीद करें कि सरकार और देश के उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा देश के तेज विकास और आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक कल्याण के मद्देनजर दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह भारत में भी बौद्धिक समझ, शोध एवं नवाचार पर अधिक धनराशि व्यय होगी'

इन दिनों देश और दुनिया में बौद्धिक सम्पदा विषयों पर प्रकाशित हो रही रिपोर्टों को पढ़ा जा रहा है। इनमें कहा जा रहा है कि भारत के तेज विकास के लिए नवाचार और बौद्धिक सम्पदा की डगर पर तेजी से बढना जरूरी है। हाल ही में अमरीकी उद्योग मंडल 'यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है, पिछले वर्ष भी भारत इसी क्रम पर स्थित था। आईपी सूचकांक के तहत शीर्ष क्रम पर जिन 10 देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन तथा स्विट्जरलैंड हैं। बौद्धिक सम्पदा में आविष्कार, रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शोध व नवाचार शामिल हैं। गौरतलब है कि इस नई आईपी रिपोर्ट में भारत की बौद्धिक सम्पदा आधारित नवाचार गतिविधियों की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि भारत बौद्धिक नवाचार के जरिये अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ाने की संभावनाओं वाला देश है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईपी मापदंड़ों के मद्देनजर भारत का आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने कॉपीराइट अधिकारों के उल्लंघन पर गतिशील निषेधात्मक आदेश जारी कर कॉपीराइट की नकल रोकने के सशक्त प्रयास किए हैं।

इसके अलावा आईपी- आधारित कर रियायतें देकर और नकली उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाकर भी भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। यदि हम बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों को देखें तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी भी देश के तेज विकास के ऊंचे लक्ष्यों के लिए बौद्धिक संपदा शोध और नवाचार में भारत को ऊंचाई प्राप्त करना जरूरी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2023 की रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत 40वें पायदान पर दिखाई दे रहा है। खास बात यह भी है कि इस सूचकांक में भारत 37 निम्न-मध्यम-आय समूह अर्थव्यवस्थाओं के बीच अग्रणी बनकर उभरा है। साथ ही भारत नवाचार के संबंध में

मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर है। बौद्धिक सम्पदा शोध एवं नवाचार की दुनिया में भारत की रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचे और डिजिटल सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। भारत आइटी सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करने में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के उद्योग-कारोबार तेजी से समय के साथ आधुनिक हो रहे हैं।

कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने जिस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया, उससे भारत कृषि विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, राजनीतिक और संचालन से जुड़ी स्थिरता, सरकार की प्रभावशीलता जैसे विविध क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। साथ ही भारत में घरेलू कारोबार में सरलता, विदेशी निवेश जैसे मानकों में भी बड़ा सुधार दिखाई दिया है। भारत की शोध एवं नवाचार ऊंचाई में अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधकरण, हाइटेक विनिर्माण और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ-साथ अटल इनोवेशन मिशन ने भी अहम भूमिका निभाई है। कोविड-19 भारत में नए चिकित्सकीय शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का भी एक अवसर बना है। भारत बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, डिजिटल, कृषि, शिक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। भारत के नवाचार दुनिया में सबसे प्रतियोगी, किफायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भारत में करीब 1.25 लाख स्टार्टअप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं। इनके आधार पर किसी देश में विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारें भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ध्यान में रखकर अपने वैश्विक उद्योग-कारोबार के रिश्तों के लिए नीति बनाने की डगर पर बढ़ती हैं। भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास और जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते हुए अमरीका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेंटर (जीआईसी) तेजी से शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तेजी से बढने से भारत में ख्याति प्राप्त वैश्विक फायनेंस और कॉमर्स कंपनियां अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। यद्यपि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार व निजी क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारत में आर एंड डी पर जीडीपी का करीब 0.67 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब दो फीसदी शोध एवं विकास में व्यय किया जाता है। यूरोपीय संघ में आर एंड डी पर जीडीपी का करीब 2 प्रतिशत तथा अमरीका, जापान और अन्य कई विकसित देशों में इस पर 3 फीसदी से भी अधिक व्यय किया जा रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार पर खर्च ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है और विश्व औसत 1.8 फीसदी से भी कम है। इस समय देश में निजी क्षेत्र का आर एंड डी पर खर्च जीडीपी के करीब 0.35 फीसदी के स्तर पर है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि सरकार बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्तमंत्री सीतारमण ने उभरते क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना करने की घोषणा की है।

हम उम्मीद करें कि सरकार अमरीकी उद्योग मंडल, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट 2024 के तहत भारत सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के वर्तमान ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने और भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक नया मॉडल बनाने की डगर पर आगे बढ़ेगी। साथ ही सरकार इस रिपोर्ट में भारत के बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को 2021 में भंग किए जाने और न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ की चिंता को दूर करेगी, क्योंकि इससे बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने की क्षमता प्रभावित होती है। हम उम्मीद करें कि सरकार और देश के उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा देश के तेज विकास और आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक कल्याण के मद्देनजर दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह भारत में भी बौद्धिक समझ, शोध एवं नवाचार पर जीडीपी की दो फीसदी से अधिक धनराशि व्यय करने की डगर पर आगे बढ़ा जाएगा। इससे जहां ब्रांड इंडिया और मेड इन इंडिया की वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।

संपादक की कलम से

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन!

क्या अद्धराज्य दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यह स्थिति 2014 में भी आई थी। तब आम आदमी पार्टी (आप) की अल्पमत सरकार थी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर आश्रित थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ही थे। वह जनलोकपाल बिल पेश करने की जिद पर थे, लेकिन उसे रोका जा रहा था। नतीजतन 49 दिन की केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चस्पां कर दिया गया। अब 2024 में स्थितियां और राजनीतिक समीकरण बिल्कुल भिन्न हैं। दिल्ली विधानसभा में 'आप' और केजरीवाल के पक्ष में 62 विधायकों का प्रचंड बहुमत है। कुल विधायक 70 होते हैं। ऐतिहासिक जनादेश वाली, विश्वास मत प्राप्त, सरकार कार्यरत है। बेशक मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में बीते 10 दिन से हैं, लेकिन उन्होंने और 'आप' प्रवक्ताओं ने बार-बार दोहराया है कि मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे। बेशक संविधान और कानून इस संदर्भ में खामोश हैं कि भ्रष्टाचार का आरोपित और हिरासत में कैद एक मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से ही सरकार चला सकता है अथवा नहीं। संविधान कई मामलों में खामोश है। शायद हमारे संविधान के रचनाकारों ने ऐसी स्थितियों की कल्पना ही नहीं की होगी! लेकिन इस तरह सरकार चलाने में कई व्यावहारिक और संवैधानिक बाधाएं तो आती हैं। संवैधानिक पद पर बैठे राजनेता की नैतिकता का भी कोई तकाजा है। 'आप' नेताओं की जो जिद है, वह असमर्थनीय और प्रतिकूल है। हिरासती मुख्यमंत्री किसी विचाराधीन सरकारी आदेश को अपनी पत्नी और वकील से भी साझा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो आदेश, उनके मंत्रियों ने, सार्वजनिक तौर पर पढ़े हैं, उन्हीं पर सत्ता के गलियारों में चर्चाएं जारी हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ही जारी किए थे? क्या मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? हिरासत में मुख्यमंत्री कोई बैठक तक नहीं कर सकते या आदेश की किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। एक साथ तीन से अधिक मुलाकाती हिरासती मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते। कैबिनेट की बैठक बुलाने का आदेश नहीं दे सकते। यदि उपराज्यपाल या मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के विचारार्थ कोई फाइल भेजते हैं, तो उसे केजरीवाल तक कौन पहुंचाएगा? गोपनीयता भंग होने के आसार पूरे हैं। लिहाजा इस संदर्भ में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का हालिया बयान बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक है। संभव है कि भारत सरकार के स्तर पर यह विचाराधीन है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की स्थितियां बन चुकी हैं? क्या दिल्ली सरकार में संवैधानिक मशीनरी अस्थिर हो गई है? अनुच्छेद 239-बी पर भी बहस शुरू हो चुकी है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली सरकार से संबंधित अनुच्छेद को बर्खास्त कर सकती हैं? फिलहाल स्थितियां मुख्यमंत्री केजरीवाल के पक्ष में हैं कि यदि वह अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो उपराज्यपाल वैकल्पिक मुख्यमंत्री के लिए उनकी पसंद जानने की कोशिश कर सकते हैं। यदि सरकार बर्खास्त कर दी गई, तो 'आप' और सरकार के भीतर मुख्यमंत्री बनने की होड़ मच सकती है। 'आप' के नेता कोई संत नहीं हैं। फिलहाल मौजूदा सरकार के लिए फरवरी, 2025 तक का जनादेश है। बहुमत की सरकार को बर्खास्त करना भाजपा के राजनीतिक पक्ष में भी नहीं होगा। ईडी, आयकर और सीबीआई को लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार शक्ति-प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस से आयकर विभाग ने कुल 3567 करोड़ रुपए का कर और जुर्माना जमा कराने का नया नोटिस भेजा है। ये दंड 1994-95, 2017-18 से 2020-21 के सालाना आयकर से जुड़ा है। यह कोई सामान्य राशि नहीं है। कांग्रेस इसे 'टैक्स टेररिज्म' के तौर पर पेश कर राजनीति करना चाहती है।

ज्ञान

शव संवाद-37

एक उड़ता हुआ पोस्टर बुद्धिजीवी के करीब आया और उसके साथ ही चलने लग पड़ा। पोस्टर पहले भी बुद्धिजीवी के आसपास से गुजरे हैं, लेकिन इस बार यह अति गतिशील था। बुद्धिजीवी आज तक वहीं का वहीं है, लेकिन तरह-तरह के पोस्टर उससे कहीं आगे निकल गए। पोस्टर की अपनी देह भाषा रही है, जिसे बुद्धिजीवी समझकर भी नहीं समझ सका। बुद्धिजीवी ने तय किया कि इस बार वह दौड़ते पोस्टर को पकड़ कर पूछ ही लेगा कि तेरी रजा क्या है। बुद्धिजीवी न देश की गति और न ही पोस्टर की प्रगति समझ पाया। वह बड़े ही आदर से पोस्टर से विनती करने लगा, 'एक पल के लिए रुक जाओ। हम आपके सेवक-आपके प्रशंसक हैं। हमारी सारी औकात लिए यूं मत भागो। हमारे पास जीने के सारे सबूत और देश का विश्वासपात्र होने का सारा जज्बा लिए यूं मत भागो।' पहली बार पोस्टर के कान खुले उसे बुद्धिजीवी की फरियाद से लगा कि उसका भी अपना साम्राज्य है। दरअसल वह भी साम्राज्यवाद की औलाद ही है। दूसरे क्षण उसे याद आया कि वह भले ही सोच ले या सोच बदल दे, लेकिन अपने ही कहे का अनुसरण नहीं कर सकता। उसे याद है कि उसके परिवार के जिन सदस्यों ने स्वच्छता का संदेश दिया, वे सारे बस स्टॉप, ऊंची इमारतों, बाजारों और गलियारों में चस्पां होकर भी नहीं बचे। धूम्रपान न करने की हिदायत देने वाले उसके सगे संबंधी पोस्टर सिगरेट सुलगाते सुलगाते मर गए। उसने कहना जारी रखा, 'हम लोगों की दुश्मनी में मर रहे हैं। कभी एक पार्टी आकर फाड़ जाती, तो कभी दूसरी उखाड़ देती। हमारे टूटते बाजू किसने देखे। किसने देखीं हमारी नम आंखें। कभी पोस्टर की चीख सुनना। हर बार हारती सरकारों के जख्म हमने सहे। बुजदिल लोग सरकार को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हम पर गुस्से से जूते बरसाते हैं। मुझे राजनीति ने बार-बार जन्म देकर मारा। व्यापार ने पुचकार कर एतबार किया, लेकिन अपनी सफलता का कभी भी मेरे साथ इजहार नहीं किया। मैंने अमिताभ बच्चन को कलेजे से लगाया, विश्व सुंदरियों को चमकाया।

एक देश एक कानून

भारत ने विभिन्न बाहरी सांस्कृतिक और धार्मिक आडम्बरो की तकलीफ को झेलने के बावजूद भी अपने हजार साला इतिहास को, संस्कार को, आचार को, विचार को, परंपरा को, और ज्ञान की शमा को विपरीत परिस्थितियों में भी अभी तक सफलतापूर्वक प्रज्जवलित कर रखा है क्योंकि इसकी संस्कृति सार्वभौमिक एवं आचार विचार सार्वकालिक है।

भारत की विचार धारा बुनियाद वसुधैव वुटुम्बकम् पर आधारित है। सत्रे भवन्तु सुखिनः सप्रे सन्तु निरामया, सने भद्राणि पश्यन्तु मा कादि दुःख भगभवेत्। यह केवल एक मंत्र है जिसका उद्देश्य नहीं है, हम इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं और वास्तव में इसका पालन भी करते हैं। शायद यही वजह रही कि जिसने इस किरायेदार को मजबूर कर दिया।

यूनान-ओ-मिस्त्र-ओ-रूमा, सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी, नाम. ओ निशां हमारा वुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-जमां हमारा इन्हीं खूबियों की वजह से आज हम सारे जहां में अतुलनीय और लाजवाब हैं। जहां सभी देश और धर्म अपने आप को श्रेष्ठ और अन्य को निम्नतर होने का दावा करते हैं, वहीं भारत ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्घोष किया और पहली बार इस विचार को जन्म दिया की जिस तरह हम अच्छे हैं उसी तरह आप लोग भी अच्छे हैं। 195 देशों में भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां लगभग हर धर्म के अनुयायी ही नहीं अपितु उसके उप-धर्मो के अनुयायी भी पूरी धार्मिक और सामाजिक आजादी के साथ जिन्दगी गुजारते रहे हैं। जिस धर्म को किसी भी देश ने जगह नहीं दिया उस को भी भारत ने सम्मानपूर्वक फलने पूलने का समान अवसर प्रदान किया है। हम इस कारण सेवुलर नहीं हैं की हमारा संविधान सेवुलर है बल्कि हमारी सनातनी विचार न केवल मनुष्यों का अत्यधिक सम्मान करना सिखाता है बल्कि इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा रचित सभी प्राणियों से स्नेह भाव रखने की प्रेरणा भी देता है। सभी धर्मो और पंथों का आदर करना हमारे टीएनए में सम्मिलित है। और ये सभी गुण भारत के संविधान में भली भांति प्रतिबिंबित हुए हैं।

यह धारणा की हम अनेक से एक हुए हैं न केवल आधारहीन बल्कि भ्रमित करने वाला भी है। हम एक से अनेक हुए हैं। जिस प्रकार एक दरख्त में उसकी शाखाएं होती हैं, उसके पत्ते होते हैं उसके टहनीयां होती हैं, उसके फल और पूल होते हैं ठीक उसी प्रकार भारत में रहने वाले सभी सनातनी थे सभी सनातनी हैं और इनशाल्लाह सनातनी ही रहेंगे। हां उनकी धार्मिक मान्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इबादत और पूजा पद्धति अलग हो सकती है। कोई सनातनी मुसलमान हो सकता है, कोई सनातनी ईसाई हो सकता है, कोई सनातनी सिख हो सकता है और कोई सनातनी यहूदी हो सकता है।

इसकी आजादी और जमानत हमारे देश का संविधान देता है। मगर वोट की राजनीति करने वालों ने इस मुस्लिम कौम को धर्म के जंजाल में इस तरह पंसा कर रखा की हम अपनी ही या अपने ही इतिहास, अपने ही परंपरा, अपने ही संस्कार और अपने ही रीति नियम से दूर होतेगए। दुर्भाग्य से यह स्थिति केवल भारत में ही देखने को मिलती है। ईरानी, इंनेशियाई, मलेशियाई और अरब इस्लाम के अनुयायी होने के बावजूद भी अपने पूर्व इस्लामी इतिहास. परंपरा और संस्कृति को नहीं भुला सके हैं और उस पर बहुत गर्व भी करते हैं।

संभवतः हम नए-नए इस्लाम में परिवर्तित हुए थे और यह साबित करना चाहते थे कि हम अरब और ईरानी से बेहतर मुसलमान हैं इसलिए हम अपने ही तहजीब और तमद्दन से अलग होते गए। यही कारण है की आज हम टोइजम के शिकार हैं। चूंकि हम कम पढ़े लिखे हैं इसलिए आसानी से गुमराह होते आ रहे हैं। हमें मुस्लिम और मोमिन में फर्व मालूम नहीं।

शरीअत का इल्म नहीं। हमने वुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ा है तो समझा नहीं, और समझा है तो उसपर अमल किया नहीं। होवूक अल एबाद और होवूक अल्लाह का फलसफा पता नहीं। इसलिए आसानी से गुमराह होते आ रहे हैं। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी यही हो रहा है।

मुसलमानों को यह कहकर भ्रमित किया जा रहा है कि आम नागरिक कानून उनकी धार्मिक गतिविधियों में भारी बदलाव लाएगा। इससे उनकी नमाज और रोजा जैसी धार्मिक प्रथाओं में वुछ बदलाव होंगे। यह इस्लाम के पांच स्तंभों में प्रवेश करके हिदू कानून लागू करेगा जो निगडित रूप से निराधार और झूठा प्रचार है। सामान्य नागरिक कानून कभी भी किसी भी धार्मिक प्रथाओं की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस की गारंटी संविधान की धारा 25 और 26 हमें देता है। यह कानून केवल विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत से संबंधित है। मैं निम्नलिखित कारणों से सामान्य नागरिक कानून की पुरजोर वकालत करता हूं।

शरीयत बनता है वुरान से, हदीस से, इज्मा और कियास से। जिन कानूनी प्रावधानों की चर्चा वुरान शरीफ में नहीं है इसका वर्णन हदीस द्वारा किया गया है। यदि कोई प्रावधान हदीसों में वर्मित नहीं है तो इसका निर्णय इस्लामी विद्वानों के बीच व्यापक परामर्श के बाद लिया जाता है। यदि इस्लामी विद्वान आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहते हैं तो अनुमान लगाया जाता है की वुरान और हदीस के अमुक शब्द या लेखन का यह तात्पर्य हो सकता है। यह इज्मा का ही परिणाम है कि आज इस्लामी न्यायशास्त्र में 5 विचारधाराएं हनफी, शापेई, मालेकी, हॅम्बली और जापेरी विकसित हुईं हैं और इनके बीच विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत प्रो. मजहर आसिफ और गोद लेने के संबंध में बहुत सारे मतभेद पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुसलमान नशे में होने के बावजूद अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो हनफी मजहब के अनुसार तलाक हो जाएगा लेकिन अन्य मजहब इसे तलाक नहीं मानते हैं। एक पत्नी जो हनफी मजहब की मानने वाली है अगर उसका पति अनिति काल से लापता है (मफवुद) तो उसको उस अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी उम्र के लोगों का निधन हो गया हो अर्थात जब उसकी उम्र 90 वर्ष के आसपास हो। हालांकि शापेई, मालेकी, हंबली मजहब के अनुसार ऐसी पत्नी को 4 साल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी। समान नागरिक कानून लागू हो जाने से हनफी-मालेकीहॅम्बली शापेई मजहब के बीच जो मतभेद हैं, समाप्त हो जाएंगे।

यह कानून सभी शहरियों को कानून के एक धागा में पिरोने का काम करेगा वोटबैंक की सियासत को खत्म करने में मददगार साबित होगा इस से महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा और उनकी स्थिति में भी सुधार आएगा जिस प्रकार पैजदारी के सभी धराएं तमाम नागरिकों पर समान रूप से लागू है ठीक इसी तरह दीवानी की धराएं भी सभी पर समान रूप से लागू होंगी जिस से भेद भाव समाप्त होगा।

इस्लामी शरीयत के मुताबिक इंसान के ऊपर दो प्रकार के हुवूक हैं। पहला हुवूक खुदा का होता है जैसे उसपर यकीन करना और उस के साथ किसी को शरीक न मानना।

उसके द्वारा भेजे गए सभी दूतों पर विश्वास करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। नमाज, रोजा, हज, जकात आदि का खालिस नियत के साथ सख्ती से पालन करना। इस हुवूक को हुवुक अल अल्लाह कहते हैं। दूसरा हुवूक इंसान का इन्सान के ऊपर होता है जिसे हुवूक अल एबाद (मानव अधिकार) कहते हैं। सूरा 4 आयात 36 में खुदा फरमाता है : अल्लाह कीइबादत करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, और माता-पिता के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों, यतीमों, मुहताजों, नजदीकी पोसियों, दूर के पड़ोसियों, अपने साथी, मुसाफिर और उन लोगों के साथ, जिनके पास तुम्हारे दाहिने हाथ हों। निस्संदेह, अल्लाह उन लोगों को पसन्द नहीं करता जो आत्म-भ्रम करते हैं और घमं करते हैं। (4:36) इसके अतिरिक्त मानव जाति के प्रति सहानुभूति, जानवरों को कष्ट न पहुंचाना, एकत्र होने का शिष्टाचार, बातचीत का शिष्टाचार, मिलने का शिष्टाचार आदि हुवूक अल एबाद में शामिल हैं। इस्लाम में हुवूक अल एबाद हुवुक अल अल्लाह से श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी स्पष्ट राय है की सामान्य नागरिक संहिता शरीयत के मोखलिफ नहीं बल्कि शरीयत के मोआफिक है। अतः इसका खुले मन और दिल से स्वागत होना चाहिए।

जब एक देश एक ध्वज, एक आधार कार्ड, एक राशन कार्ड, एक पाठ्य पुस्तक, एक स्थायी खाता संख्या, एक फौजदारी आईन हो सकता है तो एक सामान्य नागरिक संहिता क्यों नहीं? सुझाव-समाननागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सभी धर्मो के न्यायशास्त्र विशेषज्ञ और कानून विशेषज्ञ की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

सामान्य नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि यह समय की मांग है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने का यह सबसे अच्छा समय है। अनुच्छेद 14 के महत्व को समझते हुए पूरे देश में एक अनुवूल माहौल बनाया जाना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता में धर्मो और समुदाय के सवरेत्तम, वैज्ञानिक और उत्कृष्ट व्यक्तिगत कानून को शामिल करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए।

(लेखक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज एवं कल्चर, जेएनयू के पूर्व डीन हैं।।

एकाकी महिलाओं की व्यथा

डा. वरिंद्र भाटिया

इस समय एकाकीपन से परेशान महिलाओं में आत्महत्याओं में वृद्धि की खबरें आ रही हैं। यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है। कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, परंतु एक अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं पर यह बात लागू नहीं होती। कुछ समय पहले के एक अनुमान के मुताबिक भारत में तीन करोड़ 98 लाख महिलाएं एकल जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं जिनमें से आधी से अधिक गरीब हैं। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार इनमें विधवा महिलाओं की संख्या तीन करोड़ 41 लाख 62 हजार 051, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं 22 लाख 86 हजार 788 तथा अविवाहित महिलाएं या 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 33 लाख 17 हजार 719 महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं बिखरे घर, टूटे संबंधों, वैधव्य, बीमारी, बच्चों की परवरिश, अशिक्षा, सामाजिक बंधनों, शोषण, अत्याचार, दोहन, एकाकीपन, आजीविका कमाने आदि चुनौतियों से अकेली जूझ रही हैं।

कटु सत्य है कि अकेली और एकाकी महिलाओं का हमारे समाज में जीना दूभर है, चाहे वह कितनी ही समृद्ध और आत्मनिर्भर क्यों न हों। अविवाहित होकर एकाकी जीवन वाली महिलाएं भी बहुत संख्या में हैं। योग्य वर की तलाश में तो अनेक युवतियां प्रौढ़ हो जाती हैं। एकाकी जीवन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ महिलाएं समय रहते विवाह बंधन में नहीं बंध पाती। कुछ महिलाएं अपने कैरियर को संवारने में ही इतना व्यस्त रहती हैं कि उन्हें विवाह का ख्याल ही नहीं आता और जब इस बारे में वे सोचती हैं तब इतना वक्त निकल चुका होता है कि उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति नहीं होती और वे अविवाहित रहने को मजबूर हो जाती हैं। कुछ युवतियां पारिवारिक दायित्वों को निभाने में ही अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता देती हैं। आज युवा वर्ग की सोच में परिवर्तन आया है। हर कोई अपने ढंग से जिंदगी

जीना चाहता है। स्त्रियों को अपनी कल्पना का साथी नहीं मिल पाता, घरवालों को अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिल पाता, फलतः विवाह का वक्त निकलता जाता है और धीरे-धीरे उम्र खिसकने के साथ-साथ उन्हें मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। कहीं-कहीं दहेज जैसी कुप्रथा भी आड़े आ जाती है। युवावस्था तो किसी तरह निकल जाती है, पर ढलती उम्र में यह अकेलापन खटकने लगता है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। किसके लिए और क्यों जी रही हैं, यह सवाल बार-बार मन को कचोटता है। जिन भाई-बहनों और घर-परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में वे अपनी जवानी अर्पित कर देती हैं, वही भाई-बहन अपना स्थायित्व पा लेने के बाद उनसे दूर होने लगते हैं और यही अकेलापन उनके जीने की इच्छा को कम करता चला जाता है। कभी-कभी उन्हें लगता है कि यह जिंदगी बेमतलब, बेकार है। जिंदगी को वे व्यर्थ ही ढो रही हैं और यही अहसास उनके अंदर एक अवसाद-सा भर देता है और वे मानसिक रूप से बीमार होती चली जाती हैं।

वाटरलू विश्वविद्यालय में शेली बर्सिल द्वारा किए गए शोध के अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में अकेलेपन को अधिक व्यक्त करती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे आमतौर पर पुरुषों की तुलना में अधिक अकेलेपन की प्रवृत्ति रखती हैं, बल्कि महिलाएं कम प्रतिकूल परिणामों के कारण ऐसा महसूस करने लगती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों अपने मस्तिष्क की संरचनाओं के बाद भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग रणनीति अपनाते हैं, लेकिन पुरुष आम तौर पर महिलाओं की तुलना में अकेलेपन और नकारात्मकता की भावनाओं को छिपाने की अधिक कोशिश करते हैं। पुरुष इस भावना से पार पाने के लिए आम तौर पर अधिक लोगों से बात करने और अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर महिलाएं ज्यादातर जान-पहचान वाले लोगों का ग्रुप बनाने पर विश्वास नहीं करती हैं, बल्कि वे अधिक गुणात्मक संबंधों का रुख करती हैं। इस प्रकार उन्हें पुरुषों की तुलना में अन्य लोगों से जुडने में अधिक समय लगता है। टूटे रिश्तों या विवाह के मामलों में, महिलाएं शुरुआत में अकेलापन महसूस करती हैं, जबकि पुरुषों को बाद में इसका अहसास होने लगता है। यह महिलाओं की भावनात्मक प्रकृति के कारण है, जबकि पुरुष अपनी भावनाओं को तब तक छिपाने की कोशिश करते हैं जब तक वे इसे दूर करने में सफल न हो जाएं। तन्हा रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब आप महिला हों। संयुक्त परिवार में भरोसा होता है कि कोई परेशानी आएगी, तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे।

अप्रैल के पहले दिन बदल गए इन शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम, चेक करें ताजा कीमत

पेट्रोल डीजल की कीमत 1 अप्रैल 2024 आज से अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आदज सुबह 6 बजे देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम बदल गए हैं। आज भी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कुछ शहर में इनके दाम अलग है।

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अप्रैल 2024 (सोमवार) को देशभर में पेट्रोल-डीजल के रेट (Fuel Price Today) अपडेट कर दिये हैं।

बता दें कि देश के सभी शहर में फ्यूल के दाम अलग होते हैं। अगर आप भी गाड़ी की टंकी फुल करवाने जा रहे हैं तो आपको पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए।

आइए, जानते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमत (Petrol Diesel Rates) क्या है?

- महानगरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत (Petrol-Diesel Rates)
- HPCL की वेबसाइट के अनुसार देश के महानगरों में ये है फ्यूल की कीमतः
- राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.13 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

भारत में सुस्त पड़ रही सोने की डिमांड, जानिए गहनों की खरीदारी क्यों टाल रहे लोग

परिवहन विशेष न्यूज

चीन के बाद भारत में सोने की सबसे अधिक खपत होती है। हालांकि इस वक्त देश में सोने की डिमांड काफी सुस्त पड़ गई है। फरवरी के मुकाबले मार्च में गोल्ड इंपोर्ट में 90 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है। बहुत से लोगों ने या तो सोने की खरीद कम कर दी है या फिर कुछ समय के लिए टाल दी है। आइए जानते हैं कि इसकी क्या वजह है।

नई दिल्ली। भारत दुनिया में गोल्ड (gold) का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (consumer) है। लेकिन, फिलहाल यहां सोने की डिमांड काफी सुस्त हो गई है। जौहरियों का कहना है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों ने गहने-जेवरात की खरीद कम कर दी है या फिर कुछ समय के लिए टाल दी है।

कितना है सोने का वायदा भाव

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, सोमवार को भारत में सोने का वायदा भाव (gold futures) बढ़कर 69,487 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यह गोल्ड का ऑल टाइम हाई लेवल है। 2024 के शुरुआती तीन महीनों में ही इसमें 10 प्रतिशत का उछाल आ चुका है।

इसका असर देश के गोल्ड इंपोर्ट (gold imports) पर भी हुआ है। मार्च में भारत के गोल्ड इंपोर्ट में पिछले महीने के मुकाबले 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। यह कोरोना महामारी के (COVID Pandemic) सोने के आयात का सबसे निचला स्तर है।

गोल्ड प्राइस भी ऑल टाइम हाई पर

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम सोना 1,712 रुपये महंगा होकर 68,964 रुपये तक पहुंच गया है। 2024 के शुरुआती तीन महीने में सोने का भाव 5,662 रुपये बढ़ चुका है। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये पर था।

चांदी की बात करें, तो उसका दाम भी 1,273 रुपए बढ़कर 75,400 रुपये प्रति किलो हो गया है। हालांकि, इसका ऑल टाइम हाई लेवल 77,073 रुपये प्रति किलो का है, जो इसने पिछले साल 4 दिसंबर को बनाया था।

सोने के भाव में तेजी क्यों आ रही?

साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के काफी तेज रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन, दुनियाभर के कई अन्य देश मंदी की चपेट में आ सकते है। इसलिए सोने में निवेश बढ़ रहा है। शादियों के सीजन का भी गोल्ड प्राइस पर असर दिख रहा है।

90 साल का हुआ RBI : गवर्नर शक्तिकांत बोले- बढ़ रही GDP, कम हो रही महंगाई

आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का 90 वर्षगांठ को लेकर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई राजनेता और अर्थशास्त्री मौजूद है। इस समारोह में शक्तिकांत दास ने संबोधन देते हुए कहा कि देश में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल रही है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पूरे 90 साल हो गए हैं। आरबीआई के इस वर्षगांठ पर मुंबई में एक समारोह का आयोजन हुआ है। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस समारोह में संबोधन देते हुए कहा कि- देश में जीडीपी ग्रोथ में तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई दर में कमी आई है।

इसके आगे वह कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिलने है। कोविड-19 महामारी और चल रही भू-राजनीतिक स्थितियों ने भारत के साथ ही बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का परीक्षण किया है।

भारत के सुव्यवस्थित और समन्वित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों से बचाने में मदद की है। विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर है।

आरबीआई को लेकर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आरबीआई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए एक समर्थक बनने में परिवर्तित हो गया है।

हाल के वर्षों महंगाई दर में उतार-चढ़ाव की वजह से बैंकिंग सिस्टम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आज की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए आरबीआई लगातार उभरते रुझानों का मूल्यांकन कर रहा है और बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठा रहा है।

चुनाव से पहले सस्ते हुए एलपीजी सिलेंडर, अब इतनी है ताजा कीमत

LPG Price 1 April हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत रिवाइज होती है। आज से अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। महीने के पहले दिन ही सरकार ने आम जनता को राहत की खबर दी है। देशभर में कमर्शियल सिलेंडर के कीमतों में 32 रुपये की कटौती हुई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सरकार ने अप्रैल महीने के पहले दिन ही आम जनता को राहत की खबर दी है।

अप्रैल महीने के साथ ही आज से नया कारोबारी साल भी शुरू हो गया है। तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती का एलान किया है। बता दें कि महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder Price) के रेट अपडेट होते हैं।

पिछले महीने महिला दिवस (Women Day 2024) के मौके पर सरकार ने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कटौती का एलान किया था।

आज तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder Price) के दाम में 32 रुपये की कटौती की है। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कटौती हुई है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 32 रुपये सस्ता हुआ है।

बता दें कि आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम लागू हो गए है। इसका मतलब है कि अगर आप आज सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 32 रुपये की कटौती के साथ सिलेंडर मिलेगा।

चलिए, जानते हैं कि आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत क्या है।

कमर्शियल सिलेंडर का लेटेस्ट रेट

- राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1795 रुपये था। आज से इनकी कीमत 1764.50 रुपये हो गई।
- कोलकता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1911 रुपये से कम होकर 1,879 रुपये हो गई है।
- मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,749 रुपये थी। आज से इनकी कीमत 1717.50 रुपये है।
- चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 1,930.00 रुपये है।

घरेलू सिलेंडर के दाम

आज घरेलू सिलेंडर की कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर 803 रुपये है। वहीं, मुंबई में इसकी कीमत 829 रुपये और चेन्नई में 818.50 रुपये है।

मोदी सरकार ने पिछले महीने महिला दिवस पर घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती का एलान किया था। कटौती के साथ ही उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) में मिल रही सब्सिडी को भी जारी रखने की घोषणा की थी।

New Tax Regime को लेकर कहीं आपको भी तो नहीं ये गलतफहमी, वित्त मंत्रालय से समझिये सही और पूरी बात

आज से नया कारोबारी साल शुरू हो गया है। इसी के साथ आज से नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) भी डिफॉल्ट रिजीम बन गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था को लेकर कई भ्रामक जानकारी फैल रही है। इस तरह की भ्रामक जानकारी को रोकने और लोगों को सही जानकारी देने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक्स पर स्पष्टीकरण पोस्ट किया है।

नई दिल्ली: जसोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को लेकर कई भ्रामक जानकारी फैल रही है। ऐसे में इन गलत जानकारी से टैक्सपेयर को बचने के लिए वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है।

कई सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से कर व्यवस्था (Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं होगा। सोशल मीडिया पर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कई भ्रामक जानकारी फैल रही है। इस तरह की भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर स्पष्टीकरण दिया।

वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि 1 अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम बन जाएगी। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब काफी कम है पर इसमें कई तरह की डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। टैक्स डिडक्शन का लाभ पुरानी कर व्यवस्था में मिलता है।

करदाता अभी भी अपने हिसाब ले टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि अगर वो नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो वह असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल में टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के एक्स पोस्ट के अनुसार करदाता हर साल के लिए टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। वह चाहें तो एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था से पुरानी या फिर इसके विपरीत का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

आज से नहीं काम करेगा इन लोगों का PPF, NPS, Sukanya अकाउंट; क्या है वजह और कैसे करें दोबारा एक्टिव

1 अप्रैल 2024 को कई Public Provident Fund National Pension Account और Sukanya Samriddhi Account इनएक्टिव हो गए हैं। दरअसल जिन यूजर ने पिछले वित्त वर्ष में इन अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है उन सबका अकाउंट फ्रीज गया है। चलिए जानते हैं कि इन अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट कितने का होता है और इनएक्टिव अकाउंट दोबारा एक्टिव कैसे करें। पढ़े पूरी खबर..

नई दिल्ली। आज से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। इस वित्त वर्ष के शुरुआत में ही कई पीपीएफ (PPF Account), एनपीएस (NPS Account), सुकन्या (Sukanya Account) अकाउंट होल्डर का अकाउंट फ्रीज हो गया है।

इसका मतलब है कि आज से उनके अकाउंट पर मिलने वाले लाभ बंद हो गए हैं। अब ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर किस वजह से उनक अकाउंट इनएक्टिव हुआ है और अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने का प्रोसेस क्या है। आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे।

क्यों इनएक्टिव हुआ अकाउंट

नियमों के अनुसार अगर इन सभी स्कीम होल्डर एक वित्त वर्ष में अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा।

इसका मतलब है कि जिन यूजर ने पिछले वित्त वर्ष में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट किया है उनका अकाउंट इनएक्टिव नहीं हुआ है। इसके विपरीत जिन यूजर ने अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है।

बता दें कि अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो स्कीम में मिल रहे सभी लाभ भी बंद हो जाते हैं। यानी कि अगर स्कीम में टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिल रहा है तो वो भी अकाउंट के इनएक्टिव होने के बाद बंद हो जाएगी।

कितना है मिनिमम अमाउंट

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेशक एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। वहीं न्यूनतम उन्हें 250 रुपये का निवेश करना होता है।

एनपीएस (national pension system) अकाउंट में निवेशक को न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

पीपीएफ (Public Provident Fund) अकाउंट में भी निवेशक को 500 रुपये का कम से कम निवेश करना होता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है।

कैसे करें अकाउंट को एक्टिव

अगर आपका पीपीएफ, एनपीएस या फिर सुकन्या अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम राशि के साथ पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इन स्कीम में न्यूनतम राशि न जमा करने पर 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी लगती है।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का एनपीएस अकाउंट 2 साल से बंद है तो उसे इस अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 100 रुपये की पेनल्टी और न्यूनतम राशि यानी कि 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

इंश्योरेंस, ATM कार्ड से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, आज से बदल रहे हैं ये नियम...

नई दिल्ली: प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत कई प्रकार के आर्थिक और अन्य बदलावों के साथ होती है। वित्त वर्ष 2024-25 का आगाज भी कुछ इसी तरह से होने जा रहा है। आज यानी एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई प्रकार के नियम बदलने वाले हैं। इनमें बीमा पॉलिसी से लेकर NPS से जुड़े बदलाव प्रमुख हैं। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

डिजिटल बीमा खाते में जारी होगी

पॉलिसीबीमाधारकों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। इरडा के नए नियमों के अनुसार, सभी बीमा कंपनियां एक अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में ही जारी करेंगी। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसीधारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की जाएगी।

हालांकि, पॉलिसीधारकों के पास फिजिकल फार्मेट (कागजी दस्तावेज) में पालिसी लेने का विकल्प भी रहेगा। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। पॉलिसीधारक पुरानी पॉलिसी को भी डिजिटल फार्मेट में बदलवा सकेंगे।

उपराज्यपाल ने अब दिल्ली सीएम को क्यों नहीं हटाया ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। उन्हें इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? लोक सभा में दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) का कोई सांसद नहीं है. वहां सभी सात सांसद भाजपा के हैं. उप राज्यपाल के प्रतिनिधित्व वाली केंद्र सरकार का वास्तविक लक्ष्य है राज्य सरकार की विश्वसनीयता को प्रभावित करना. आमतौर पर यह काम पार्टी की प्रदेश इकाई का होता है. इस मामले में भाजपा की दिल्ली इकाई इतनी निष्प्रभावी है कि उसे इस काम के लिए संवैधानिक मुखिया की मदद लेनी पड़ी जबकि यह काम निर्वाचित नेताओं का था.

वी के सक्सेना को मेधा पाटकर पर केस करना पड़ा था भारी

विनय कुमार सक्सेना को 2022 में दिल्ली का उप राज्यपाल बनाया गया था. इससे पहले 2015 में उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का अध्यक्ष बनाया गया था. मूल रूप से कानपुर के रहने वाले सक्सेना ने अपना करियर राजस्थान की एक निजी कंपनी में सहायक अधिकारी के रूप में शुरू किया था. सन 1995 में वह धोलेरा बंदरगाह परियोजना के महा प्रबंधक बनकर गुजरात चले गए जिसे अदाणी पोर्ट्स लिमिटेड और जे के व्हाइट सीमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा था। उन्हें न केवल सीईओ बनाया गया बल्कि परियोजना का निदेशक भी बना दिया गया. वर्ष 2000 से आज तक सक्सेना को अगर किसी से डर लगा है तो वह हैं मेधा पाटकर. सन 1990 के दशक में जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध बाबा आमटे और मेधा पाटकर के नेतृत्व वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन चरम पर था उस समय सक्सेना ने एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था नैशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल). उन्होंने आलेख प्रकाशित कराने आरंभ किए और पाटकर की गतिविधियों के विरुद्ध सशुल्क विज्ञापन देने शुरू किए. उन्होंने आरोप लगाया कि वह राष्ट्र विरोधी हैं तथा उन्हें संदिग्ध विदेशी माध्यमों से पैसे मिल रहे थे. पाटकर की मांगें एकदम साधारण थीं: बांध की ऊंचाई बढ़ाने से निश्चित तौर गुजरात और राजस्थान के कई जल संकट वाले इलाकों की प्यास बुझाने में मदद मिलती लेकिन इससे मध्य प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को अपने घरों से उजडना पड़ता.

बांध की ऊंचाई बढ़ाने तथा जल भराव वाले इलाके का विस्तार करने से पहले इन लोगों का पुनर्वास करना जरूरी था. इन दलीलों के सही गलत होने से परे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक समय गुजरात में बदनाम हो गया था. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने रुख के समर्थन में हरसंभव सहायता जुटाने की कोशिश की. राज्य सरकार की ओर से सक्सेना ने बीड़ा उठाया और पाटकर के खिलाफ मुकदमा लड़ा. बदले में पाटकर ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले दायर किए जो अभी भी चल रहे हैं. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय काम के लिए सक्सेना का समर्थन यहीं नहीं रुका. उनके स्वयंसेवी संगठन ने ही चिंतक आशिष नंदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी. उनका आरोप था कि 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद नंदी ने एक लेख लिखा था जिसने राज्य की 'छवि खराब' की थी और 'हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दुर्भावना' बढ़ाई.

प्रतिवाद में नंदी ने कहा कि यह प्राथमिकी दुर्भावना के साथ दर्ज कराई गई है और उन्हें उनके विचार व्यक्त करने के लिए दंडित करने की कोशिश की जा रही है. गुजरात पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई और आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में नंदी को राहत प्रदान की.

सक्सेना के कार्यकाल में ही केवीआईसी को कॉर्पोरेट में बदला गया और उसने मुनाफा कमाया परंतु यह आदेश भी था कि उसके कर्मचारी आजीवन खादी के बने कपड़े पहनेंगे. सक्सेना के नेतृत्व में केवीआईसी ने प्रमुख कपड़ा ब्रांड मसलन रेमंड्स और अरविंद मिल्स के साथ अनुबंध किए ताकि खादी की मार्केटिंग की जा सके.

2017 में पहली बार फैब इंडिया जैसी कंपनियों और एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों को ट्रेडमार्क के उल्लंघन का कानूनी नोटिस दिया गया क्योंकि ये कंपनियां और प्लेटफॉर्म जिन कपड़ों को खादी के नाम से बेच रहे थे वे खादी नहीं थे और 'उन पर केवीआईसी द्वारा जारी टैग या लेबल नहीं लगा था.' **मुकदमों का इतना अनुभव होने के बाद भी वह कौन सी बात है जो सक्सेना को केजरीवाल को पद से हटाने के लिए कानून का इस्तेमाल करने से रोक रही है? शायद इसका जवाब 25 मई के बाद मिलेगा.की स्थिति में कांग्रेस आज नहीं है।यही कारण है कि कांग्रेस ने तृत्व ने केजरीवाल का साथ देने का निर्णय किया होगा।**

1 अप्रैल से मंहगी हुई शराब,तो थोडी-थोडी पिया करो....

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

मरहूम गजल गायक पंकज उधास ने सालों पहले अपनी गजल शराब के शौकीनों को सलाह दी थी। गजल में बाकायदा शराब के शौकीनों से गुजारिश की। हुई मंहगी बहुत शराब, तो थोडी-थोडी पिया करो। सरकार ने आज- - 1 अप्रैल से ,बीयर,देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में बढोतरी कर दी है ।बता दें कि शराब की कीमतों में इजाफे की वजह आज से नया वित्त-वर्ष शुरू हो गया है ।इसके साथ ही नई एक्साइज पॉलिसी भी लागू हो गई है। इससे पूरे देश में बीयर,देसी और अंग्रेजी तीनों प्रकार की शराब की कीमतों में इजाफा हुआ है।

उत्तर प्रदेश,छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश तीनों राज्यों में सरकारों ने शराब के नए रेट जारी भी कर दिए है। यहां तक कि शराब के ठेकेदारों को भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। बडे हुए रेट आज सोमवार से लागू हो गए है ।आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कडी कारवाई करने का निर्देश है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गत 29 जनवरी को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिली थी ।मोदी केबिनेट ने इस पर मोहर लगाई थी ।नई आबकारी नीति के तहत देश में शराब लाईसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ गई। इसके साथ ही एक्साइज रेट भी बढाया गया है ।इस वजह से ही देश में 1 अप्रैल से शराब और बीयर मंहगी हो गई है ।बता दें कि केंद्र सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत अगले वित वर्ष में करीब 45 हजार करोड रूपये कमाने का लक्ष्य तय किया है ।इससे पहले शराब रेटों में साल 2022 में बढोतरी की थी। 1 अप्रैल से उतर प्रदेश में देसी शराब का पव्वा 5 रूपये मंहगा हुआ है ।यह अब 65 रूपये की जगह 70 रूपये का मिलेगा ।दूसरे प्रकार का पव्वा 75 रूपये से बढकर 90 रूपये का मिलेगा ।अंग्रेजी शराब का का क्वार्टर 15-20 रूपये मंहगा हुआ है। वहीं हॉफ और फुल बोतल भी मंहगी मिलेगी ।बीयर के केन में 10 रूपये बढा है ।बोतल के दामों में 20 रूपये की बढोतरी हुई है। वही मध्यप्रदेश में पव्वे से लेकर बोतल कैन के दामों में 10 से 40 रूपये का इजाफा हुआ है ।सबसे बडी बात ये है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लगाए गए सभी सेस हटा दिए है। कोरोना काल के वक्त लगाए गए सभी टैक्स हटा दिए है। राज्य सरकार को आगामी वित्त वर्ष के लिए 11 हजार करोड का राजस्व जुटाने का टार्गेट मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में शराब के दामों में 150 से लेकर 200 रूपये का इजाफा हुआ है। यहां 15 % का इजाफा किया गया। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को नए वित वर्ष के लिए करीब 15 हजार करोड रूपये राजस्व का टार्गेट मिला है ।अकेले भोपाल के लिए 916 करोड रूपये का टार्गेट मिला है।

भारत के 7 सबसे अमीर बाबा? रामदेव, सद्गुरु से भी अमीर ये गुरू, जानें किसके पास है 10000 करोड़ की अकूत धन-दौलत

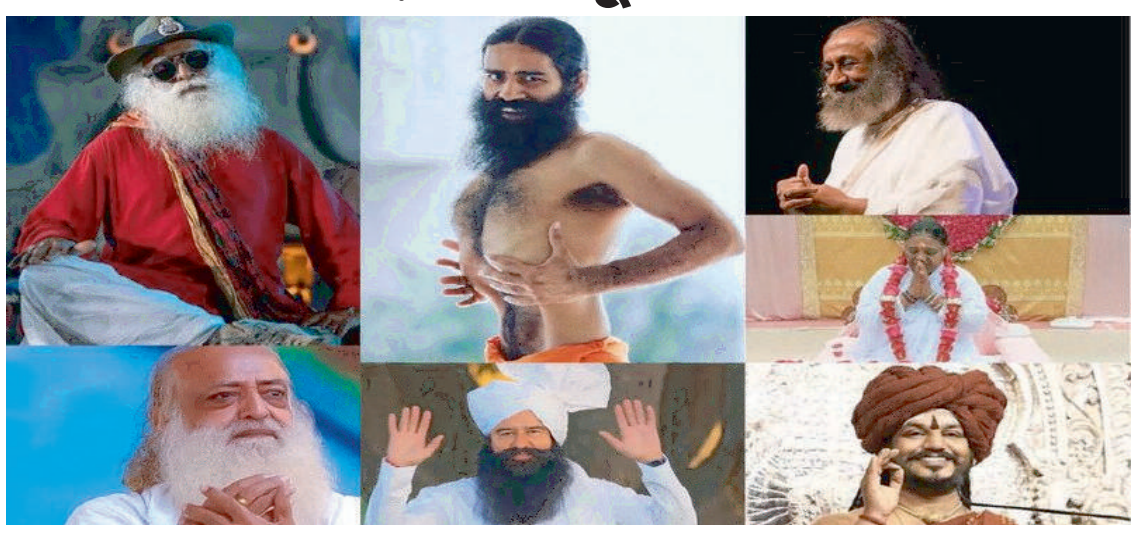

भारत में अध्यात्म का बड़ा महत्व है और यही वजह है कि देश में बड़ी संख्या में गुरुओं और बाबाओं की मौजूदगी है। बड़े रसूख वाले इन बाबाओं के महंगे व हाई-प्रोफाइल आश्रमों में भक्तों की भीड़ लगती है। दुनियाभर में लाखों फॉलोअर्स वाले इन आध्यात्मिक गुरुओं के पास अकूत धन-दौलत है। आज हम आपको बताएंगे भारत के 7 सबसे धनी और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं और बाबाओं की संपत्ति के बारे में

सद्गुरु जग्गी वासुदेव जाने-माने आध्यात्मिक और योगा गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव Isha Foundation के फाउंडर हैं। वह देश-दुनिया के सबसे बड़े बाबाओं में से एक हैं। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 2023 में उनकी नेट वर्थ 18 करोड़ रुपये थी। उनके बड़े साम्राज्य में कई योगा सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ईकोलॉजिकल प्रोजेक्ट हैं जिसके चलते वह काफी प्रभावशाली हुए हैं।

श्री श्री रवि शंकर श्री श्री रवि शंकर जाने-माने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं। दुनियाभर में अध्यात्म के जरिए लोगों की जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए उन्हें जाना जाता है। खबरों के मुताबिक, 151 से ज्यादा देशों में उनके 300 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी ख्याति देश-दुनिया में फैली हुई है। इंडिया टुडे के मुताबिक, श्री श्री रवि शंकर ने 6 साल कु उम्र में वैदिक साहित्य की पढ़ाई शुरू की थी। और 17 बरस के होने पर अपनी शिक्षा पूरी कर ली। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उनकी नेट वर्थ करीब 1000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा वह कई हेल्थकेयर सेंटर, फार्मेसी और आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के मालिक भी हैं।

बाबा रामदेव बाबा रामदेव एक सफल योग गुरू और कारोबारी हैं। भारत में पतंजलि आयुर्वेद के जरिए उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। इसके साथ देश-दुनिया में योग को प्रसारित किया। हरियाणा के किसान परिवार से आने वाले रामदेव ने हरिद्वार में योग सिखाना शुरू किया था। फिलहाल वह पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के मुखिया हैं। इन दोनों ट्रस्ट की देशभर में कई ब्रांचेज हैं। उनकी नेट वर्थ करीब 1600 करोड़ रुपये है।

माता अमृतानंदमयी अम्मा माता अमृतानंदमयी को प्यार से लोग अम्मा बुलाते हैं। वह केरल से हैं और उनका जन्म 27 सितंबर 1953 को हुआ था। वह अमृतानंदमयी ट्रस्ट की मुखिया हैं और TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास 1500 करोड़ रुपये की वैल्यू के एसेट्स हैं।

गुरमीत राम रहीम सिंह राम रहीम की गिनती आज भी देश के सबसे धनी बाबाओं में होती है। 1990 से लेकर अब तक डेरा सच्चा सौदा के मुखिया रहे राम रहीम के हजारों फॉलोअर्स हैं। राम रहीम सिंह की अनुमानित नेट वर्थ करीब 1455 करोड़ रुपये है।

आसाराम बापू आसाराम बापू के दुनियाभर में 350 आश्रम और 17000 बाल संस्कार केंद्र हैं। 2021 की बात करें तो ट्रस्ट ने कुल 350 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट किया था।

स्वामी नित्यानंद स्वामी नित्यानंद ने नित्यानंद ध्यानपीठम फाउंडेशन की शुरुआत की थी। यह फाउंडेशन मंदिर, गुरुकुल और आश्रम चलाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वामी नित्यानंद की नेट वर्थ करीब 10,000 करोड़ रुपये है।

डायबिटिक न्यूरोपैथी के क्या है लक्षण जिनकी पहचान कर शुरुआत में ही डायबिटिक न्यूरोपैथी का पता लगाया जा सकता है, जाने

डायबिटीज की बीमारी होने पर लोगों का ब्लड शुगर बढ़ जाता है और जिंदगीभर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ती है. डायबिटीज के मरीजों का शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाए और लंबे समय तक ऐसा रहे, तो इससे नसें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. जब हद से ज्यादा शुगर लेवल की वजह से नर्व डैमेज होने लगती हैं, तब इस कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है. जब हमारे शरीर के किसी हिस्से की नर्व डैमेज हो जाती है, तब नसें उस हिस्से में सिग्नल भेजना बंद कर देती हैं. इसकी वजह से शरीर का अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाता है. यह बेहद खतरनाक कंडीशन होती है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है. इसे लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए.

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन की रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज के करीब 50 प्रतिशत मरीजों को डायबिटिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है. नर्व डैमेज के कई लक्षण होते हैं, जिनकी पहचान कर सही समय पर ब्लड शुगर कंट्रोल कर लिया जाए, तो ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता है. अगर डायबिटीज के मरीज लंबे समय तक अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लें, तो नर्व डैमेज से बचा जा सकता है. डायबिटीज की

वजह से होने वाली नर्व डैमेज के 4 टाइप होते हैं. पहला पेरीफेरल नर्व डैमेज, दूसरा ऑटोनोमिक नर्व डैमेज, तीसरा प्रॉक्सिमल नर्व डैमेज और चौथा फोकल नर्व डैमेज. सभी तरह की नर्व डैमेज में शरीर के अलग-अलग अंग प्रभावित होते हैं. हाई शुगर लेवल से आमतौर पर नर्व डैमेज हाथ-पैर, आंख, हार्ट, पेट, ब्लैडर और प्राइवेट पार्ट जैसे हिस्सों में होती है. डायबिटिक न्यूरोपैथी के कई लक्षण होते हैं, जिनकी पहचान कर शुरुआत में ही डायबिटिक न्यूरोपैथी का पता लगाया जा सकता है. हाथ-पैर सुन्न होना, हाथ-पैरों में चुभन होना, फुट अल्सर होना, जॉइंट पेन, मतली, उल्टी, डायरिया, भूख न लगना, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत, हिप में सीवियर पेन, आंखों के पीछे दर्द होना, विजन ब्लर होना जैसे लक्षण नजर आएं, तो सावधानी बरतें. हालांकि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप रोजाना अपने ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करें. अगर आपको शुगर लेवल अनकंट्रोल होता नजर आए, तो डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करें. इसे लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें, वरना समस्या बढ़ सकती है. एक बार नर्व डैमेज हो जाए, तो उसे रिवर्स करना संभव नहीं होता है. इसलिए इसे लेकर अत्यंत सावधानी बरतें. अब सवाल उठता है कि ब्लड शुगर को किस तरह कंट्रोल किया जाए? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट लेनी चाहिए और नियमित फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. इसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट्स को अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए और बीपी भी कंट्रोल रखना चाहिए. ऐसे मरीजों को एल्कोहल और स्मोकिंग को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा डॉक्टर की दी गई दवाइयां समय पर लेनी चाहिए. रोजाना अपने ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए. इन सभी बातों को फॉलो कर शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है.

अब आप जान ले कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने की कोई दवा नहीं ! अचानक बीपी कम होने पर तुरंत करें ऊपर बताए 5 उपाय, बच जाएगी जिंदगी।

देशभर में लागू हुआ वन व्हीकल, वन फास्टैग, जानें क्या होगा असर

भारत में नेशनल हाइवे और एक सप्रेसवे पर सफर के समय FASTag को अनिवार्य पहले ही किया जा चुका है। लेकिन आज से पूरे देश में One Vehicle One FASTag को भी लागू कर दिया गया है। नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से One Vehicle One FASTag को लागू किए जाने के बाद क या असर हो सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने के साथ ही इनको बनाने वाली संस्था NHAI की ओर से एक अप्रैल 2024 से One Vehicle, One FASTag को लागू कर दिया गया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि One Vehicle, One FASTag को लागू करने के बाद क्या असर होगा।

लागू हुआ One Vehicle, One FASTag

नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया की ओर से जानकारी दी गई है कि पूरे देश में एक वाहन, एक फास्टैग को लागू कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उद्देश्य 'एक वाहन, एक फास्टैग' के जरिए सिर्फ एक फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा देना है।

एक से ज यादा फास टैग का नहीं कर पाएंगे उपयोग

अधिकारी ने बताया कि एक से ज्यादा फास्टैग अब काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं, वे आज यानि 1 अप्रैल 2024 से उन सभी का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

बढ़ाई थी समयसीमा

Paytm FASTag उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को देखते हुए NHAI ने 'एक वाहन, एक FASTag' पहल अनुपालन की समय सीमा मार्च के अंत तक बढ़ा दी थी। लेकिन आज से नए वित्त वर्ष की शुरूआत होने के साथ ही एनएचएआई की ओर से इसे भी लागू कर दिया गया है। पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के ग्राहकों और व्यापारियों को 15 मार्च तक अपने खाते दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी थी।

आठ करोड़ से ज यादा हैं यूजर्स

FASTag के जरिए देशभर के नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लिया जाता है। इस संग्रह प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से संचालित किया जाता है। मौजूदा समय में देशभर में करीब आठ करोड़ से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। यह सीधे टोल मालिक से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का उपयोग करता है।

भारतीय संस्कृति और इतिहास की झलक मिलती हैं इन प्राचीन गुफाओं में

परिवहन विशेष न्यूज

भारत का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन इतिहास में से एक है। यह अपने में सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति के अंश समेटे हुए है। हो भी क्यूं ना। यहां पर पनपी सभ्यता और संस्कृति ना सिर्फ विशेषताओं की धनी है बल्कि अपने में हजारों रंगों को समेटे है। भारतीय संस्कृतियों की झलक ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों और प्राचीन गुफाओं में भी देखने को मिल जाएंगी। भारत के जंगलों और घाटियों के बीच स्थित पत्थर की संरचनाओं में भी भारतीय सभ्यता के पुट पटे पड़े हैं। देखने में बिलकुल रहस्मयी और आकर्षक। जी हां भारत की इतिहास को ब्यान करती ये गुफाएं अपने में असाधारण कलाकृतियों और नक्काशियों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भारत में ऐसे कई सारी गफाएं हैं, जिन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वाहक कहा जा सकता है। तो चलिए आज इन्हीं वाहकों के बारे में बाते करते हैं।

बाघ की गुफाएं, मध्यप्रदेश-

बाघ गुफाएँ भारत के मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित नौ शिलालेखित गुफाएँ हैं। ये गुफाएँ अपनी प्राचीन बौद्ध स्तूपों, चित्रकला, और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो पाँचवीं से सातवीं सदी ईसा पूर्व तक दिखाई गई है। यह प्राचीन भारतीय शिल्प और कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन्हें एक बालुका की चट्टान से निकाला गया है और माना जाता है कि ये गुप्तकालीन काल में बनाई गई थीं और फिर वाकाटका राजवंश के काल में विस्तारित की गई थीं।

बाघ की गुफाएँ विभिन्न बौद्ध विषयों की जटिल नक्काशियों और मूर्तियों को दर्शाती हैं, जैसे कि बुद्ध का जीवन, बोधिसत्त्व, और अन्य पौराणिक पात्र। गुफाओं की दीवारों पर जीवंत चित्रकला से सजी हुई पेंटिंग हैं, जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती हैं।

इस स्थल को ब्रिटिश अफसर जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। तब से, बाग़ गुफाएँ विद्वानों, इतिहासकारों, और पर्यटकों को आकर्षित करती आ रही हैं। यह आज भी ऐतिहासिक और कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो भारतीय परंपरा और विरासत को दर्शाती हैं।

बादामी गुफाएं, कर्नाटक-

बादामी गुफाएं, भारत के कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित हैं। ये छःवीं सदी

ईसापूर्व में बनाई गई शिलालेखित गुफा मंदिर हैं। बादामी चट्टानों से निकाले गए इन गुफाओं में प्राचीन चालुक्य शैली की महत्वपूर्ण वास्तुकला है। यहँ पर चार मुख्य गुफाएँ हैं जो हिंदू और जैन देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें विभिन्न पौराणिक दृश्य और देवताओं की अलंकरण और संगमरमर की मूर्तियाँ हैं। इन गुफाओं में खूबसूरत छत की चित्रकला भी है, खासकर गुफा 3 में, जो अपने विष्णु की अवतारों की भव्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। बादामी गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और प्राचीन भारतीय कला और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है।

उदयगिरि गुफाएँ, उड़ीसा-

उदयगिरि गुफाएँ भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर शहर के पास स्थित प्राचीन शिलालेखित गुफाओं का एक पुराना समूह है। इनके निर्माण की तारीख लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। ये जैन वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उदयगिरि गुफाएँ बालूका पहाड़ियों से निकाली गई हैं, जिनमें कई गुफाएँ शिलालेखों और बेहतरीन मूर्तियों से सजी हुई हैं, जो जैन देवताओं, तीर्थंकरों, और जैन पौराणिक कथाओं की चित्रित गाथाओं को दिखाती हैं। इन गुफाओं में अलंकृत द्वार, स्तंभ, और मोतिफ भी हैं, जो प्राचीन शिल्पकारों की कुशलता और कारीगरी का प्रदर्शन करते हैं। रानी गुम्फा (रानी की गुफा) उल्लेखनीय गुफाओं में से एक है, जिसकी अलंकारिक नक्काशियाँ और दो मंजिले भवन इसे प्रसिद्ध बनाते हैं। उदयगिरि गुफाएँ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं और उड़ीसा तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण हैं।

एलिफ़ेंटा गुफाएँ, महाराष्ट्र-

महाराष्ट्र के मुंबई हार्बर में स्थित एलिफ़ेंटा आइलैंड पर स्थित एलिफ़ेंटा गुफाएँ, 5वीं से 8वीं सदी ईसापूर्व की प्राचीन शिलालेखित गुफाओं का एक प्राचीन समूह है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध, इन गुफाओं के शानदार मूर्तियों और वास्तुकला प्रमुखतः भगवान शिव को समर्पित हैं। मुख्य गुफा, जिसे महान गुफा या गुफा 1 के रूप में जाना जाता है, में शिव की विभिन्न रूपों की विशालकाय मूर्तियाँ हैं, जिसमें तीन सिरों वाले त्रिमूर्ति भी शामिल है। आइलैंड पर अन्य गुफाएँ हिन्दू पौराणिक कथाओं की विभिन्न दृश्यों को चित्रित करने वाली पेशेवर नक्काशियाँ प्रदर्शित करती हैं। एलिफ़ेंटा गुफाएँ दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की झलक प्रदान करती हैं और प्राचीन भारतीय कुशलता और कलाकृति का साक्षात्कार कराती हैं।

भारतीय इतिहास और संस्कृति को पेश करती ये गुफाएं वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों के बीच हमेशा से ही कौतुहल का विषय रही हैं। इन गुफाओं की अहमियत को देखते हुए ही इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर संरक्षित किया जाता है। आप को भी जब कभी अवसर मिले अपनी सभ्यता और संस्कृति के इन धरोहर को जानने और समझने से ना चूकें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023